



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17042020-219069
CG-DL-E-17042020-219069

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2020/चैत्र 28, 1942

No. 146]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2020/CHAITRA 28, 1942

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2020

दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020

(2020 का 4)

फा. सं. 6-19/2019 & चैत्र 28, 1942.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (iii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) में एक और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः

1. (i) इन विनियमों को दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020 (2020 का 4) कहा जाएगा।
(ii) ये विनियम 01 मई, 2020 से लागू होंगे।
2. दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) (इसमें आगे इन्हें मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 4 में खंड (v) के बाद निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा: “(vi) प्रत्येक बीएसओ, सीएमएसपी, यूएसपी और यूनीफाइड लाइसेंस (यूएल) लाइसेंसधारक गैर-भेदपूर्ण तरीके से और अनुसूची 1 में निर्दिष्ट सीमा के भीतर अपने नेटवर्क पर समाप्त होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स के लिए समापन प्रभार पेश करेंगे।”
3. मूल विनियमों की अनुसूची 1 में, पैराग्राफ 1 में कॉलम “समापन प्रभार” के अंतर्गत तालिका में “0.30 रु. (मात्र तीस पैसे) प्रति मिनट” शब्दों और अंकों को “0.35 रु. (मात्र पैंतीस पैसे) प्रति मिनट से कम नहीं और 0.65 रु. (मात्र पैंसठ पैसे) प्रति मिनट से अधिक नहीं” शब्दों और अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

एस. के. गुप्ता, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./07/2020]

टिप्पणी 1: मूल विनियम दिनांक 29.10.2003 को फाइल संख्या 409-5/2003-एफएन (2003 का 4) के तहत और बाद के संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के तहत प्रकाशित किए गए थे:

- (i) 25.11.2003 का 409-5/2003-एफएन (2003 का 5) (पहला संशोधन);
- (ii) 12.12.2003 का 409-5/2003- एफएन (2003 का 6) (दूसरा संशोधन);
- (iii) 31.12.2003 का 409-5/2003-एफएन (2003 का 7) (तीसरा संशोधन);
- (iv) 06.01.2005 का 409-8/2004-एफएन (2005 का 1) (चौथा संशोधन);
- (v) 11.04.2005 का 409-8/2004-एफएन (2005 का 7) (पांचवां संशोधन), जिसे 2005 की अपील संख्या 7 पर माननीय टीडीएसएटी ने अपने दिनांक 21.09.2005 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था;
- (vi) 23.02.2006 का 409-5/2005-एफएन (2006 का 1) (छठा संशोधन);
- (vii) 10.03.2006 का 409-5/2005-एफएन (2006 का 2) (सातवां संशोधन);
- (viii) 21.03.2007 का 409-2/2007-एफएन (2007 का 2) (आठवां संशोधन);
- (ix) 27.03.2008 का 409-22/2007-एफएन (2008 का 2) (नौवां संशोधन);
- (x) 09.03.2009 का 409-12/2008-एफएन (2009 का 2) (दसवां संशोधन);
- (xi) 23.02.2015 का 409-8/2014-एनएसएल-1 (2015 का 1) (ग्यारहवां संशोधन);
- (xii) 24.02.2015 का 409-8/2014-एनएसएल-1 (2015 का 2) (बारहवां संशोधन);
- (xiii) 19.09.2017 का 10-8/2016-बीबीएंडपीए (2017 का 5) (तेरहवां संशोधन);
- (xiv) 12.01.2018 का 10-8/2016-बीबीएंडपीए (2018 का 2) (चौदहवां संशोधन);
- (xv) 17.12.2019 का 6-14/2019-बीबीएंडपीए (2019 का 10) (पंद्रहवां संशोधन)।

टिप्पणी 2 व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020 (2020 का 4) के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट किया गया है।

“दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020” के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन

क. इंटरकनेक्शन

1. इंटरकनेक्शन का तात्पर्य ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी व्यवस्थाओं से है, जिनके अंतर्गत सेवा प्रदाता अपने उपभोक्ताओं को दूसरे सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं, सेवाओं और नेटवर्क के लिए एक्सेस देने के लिए अपने उपकरणों, नेटवर्क और सेवाओं को कनेक्ट करता है।
2. इंटरकनेक्शन उपभोक्ता के नजरिये से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ता या नेटवर्क ऑपरेटर इंटरकनेक्शन व्यवस्था के बिना सेवाओं, जिनकी वे मांग करते हैं, को प्राप्त नहीं कर सकते या आपस में संवाद नहीं कर सकते। नेटवर्क ऑपरेटरों के बीच इंटरकनेक्शन को सुगम बनाने के लिए व्यावसायिक और तकनीकी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए कुछ मुद्दों पर ऑपरेटरों की सहमति होनी चाहिए और विनियामक द्वारा तय किए जाने चाहिए। इंटरकनेक्शन व्यवहारिक प्रतिस्पर्धा के आधारों में से एक है और दूरसंचार क्षेत्र के उचित विकास के लिए यह बेहद जरूरी है।

ख. इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (आईयूसी)

3. इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (आईयूसी) सफल इंटरकनेक्शन व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक मुद्दा है। आईयूसी के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है:

(1) घरेलू समापन प्रभार

4. घरेलू समापन प्रभार (डीटीसी) वो प्रभार है जो पहुंच प्रदाता, जिसके नेटवर्क पर कॉल शुरू होता है, के द्वारा पहुंच प्रदाता जिसके नेटवर्क में कॉल समाप्त होता है, को देय होता है। कॉलिंग-पार्टी-पे (सीपीपी) व्यवस्था में कॉलिंग उपभोक्ता कॉल के लिए अपने पहुंच प्रदाता को भुगतान करता है और कॉलिंग पार्टी का पहुंच प्रदाता आमतौर पर नेटवर्क उपयोग लागत को कवर करने के लिए कॉल पार्टी के पहुंच प्रदाता को समापन प्रभार का भुगतान करता है।

(2) अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार

5. अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार वो प्रभार है जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर (आईएलडीओ) द्वारा देय होता है, यह ऑपरेटर विदेश से आने वाली कॉल को देश में पहुंच प्रदाता, जिसके नेटवर्क पर कॉल समाप्त होती है, तक पहुंचाता है।

- (3) ट्रांजिट प्रभार
6. जब दो दूरसंचार नेटवर्क सीधे जुड़े नहीं होते हैं, तो वे एक मध्यवर्ती नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से समापन नेटवर्क पर कॉल भेजी जाती है। ऐसे मध्यवर्ती नेटवर्क को ट्रांजिट नेटवर्क कहते हैं और इंटरकनेक्शन/नेटवर्क उपयोग लागत को कवर करने के लिए ट्रांजिट नेटवर्क को अदा किए जाने वाले प्रभार को ट्रांजिट प्रभार कहते हैं।
- (4) कैरिज प्रभार
7. भारत में पहुंच प्रदाता लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए), इन्हें सर्कल भी कहा जाता है, में पहुंच सेवाओं की पेशकश कर सकता है; इसके लिए इंटर-सर्कल ट्रैफिक को राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर (एनएलडीओ) के माध्यम से संचालित करना अपेक्षित होगा। इंटर-सर्कल कॉल्स को कैरी करने की लागत को कवर करने के लिए किसी पहुंच प्रदाता द्वारा एनएलडीओ को अदा किए जाने वाले प्रभार को कैरिज प्रभार कहते हैं।
- (5) ओरिजिनेशन प्रभार
8. कॉलिंग पार्टी का पहुंच प्रदाता लागू टैरिफ के अनुसार कॉलिंग पार्टी (यानी उपभोक्ता) से कॉल प्रभार लेता है। उपभोक्ता से ली गई इस रकम में से पहुंच प्रदाता को कॉलिंग पार्टी के पहुंच प्रदाता को समापन प्रभार और एनएलडीओ को कैरिज प्रभार (इंटर-सर्कल कॉल के मामले में) का भुगतान करना होता है। पहुंच प्रदाता कॉल को प्रारंभ करने की लागत को कवर करने के लिए शेष रकम को अपने पास रखता है। कॉलिंग पार्टी के पहुंच प्रदाता द्वारा अपने पास रखी गई इस रकम को ओरिजिनेशन प्रभार कहते हैं। भारत में विनियामक द्वारा ओरिजिनेशन प्रभार निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं और ये फोरबेयरस में रखे गए हैं।
- (6) अंतर्राष्ट्रीय निपटान प्रभार
9. अंतर्राष्ट्रीय निपटान प्रभार वे प्रभार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक का आदान-प्रदान करने के लिए विदेशी सेवा प्रदाताओं और भारतीय आईएलडीओ के बीच आदान-प्रदान किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निपटान प्रभार में अंतर्राष्ट्रीय कैरिज प्रभार, राष्ट्रीय कैरिज प्रभार (यदि कोई हो) और घरेलू समापन प्रभार शामिल हैं।
- ग. भारत में आईटीसी के लिए विनियामक व्यवस्था का क्रमिक विकास
10. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसके बाद, जिसे भादूविप्रा या प्राधिकरण कहा गया है) ने 24.01.2003 के 'दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम, 2003 (2003 का 1)' के माध्यम से आईटीसी सहित इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क स्थापित किया था। आईयूसी को और बेहतर और सुगम बनाने लिए, प्राधिकरण ने 29.10.2003 को 'दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम, 2003 (2003 का 4)' जारी किया। इस विनियम ने दिनांक 24.01.2003 के आईयूसी विनियम की जगह ली और 01.02.2004 से लागू हुआ और यह आज की तिथि में देश में मूल आईयूसी विनियम है। इसके प्रारंभ से लेकर अभी तक इसमें 15 (पंद्रह) संशोधन किए जा चुके हैं।
11. '29.10.2003 के 'दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम, 2003 (2003 का 4)' के माध्यम से प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ आईटीसी की दर 0.30 रु. प्रति मिनट निर्धारित की थी। तब से, प्राधिकरण ने आईटीसी में तीन संशोधन किए हैं:
- क) दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम, 2009 द्वारा आईटीसी की दर 01.04.2009 से 0.40 रु. प्रति मिनट की गई और
- ख) दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2015 द्वारा आईटीसी की दर 01.03.2015 से 0.53 रु. प्रति मिनट की गई और
- ग) दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2018 (इसके बाद इसे आईयूसी विनियम, 2018 कहा गया है) के द्वारा आईटीसी की दर 01.02.2018 से 0.30 रु. प्रति मिनट की गई।
- घ. आईटीसी की मौजूदा समीक्षा
12. 2018 में आईटीसी के निर्धारण में शामिल मुद्दों का विश्लेषण करते समय प्राधिकरण ने निम्नानुसार टिप्पणी की:
- क) अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग वॉइस ट्रैफिक को कैरी करने के लिए कैरियर रूट को ओवर-द-टॉप (ओटीटी) रूट और ग्रे रूट से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है; और
- ख) कैरियर रूट के जरिये इंटरनेशनल इनकमिंग वॉइस ट्रैफिक में वित्त वर्ष 2016-17 से कमी आनी प्रारंभ हो गई है।
13. प्राधिकरण ने यह भी टिप्पणी की कि अगर अंतरपणन अवसर यानी घरेलू वॉइस कॉल के लिए आईटीसी और टैरिफ के बीच अंतर को भरा जाता है या न्यूनतम रखा जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग वॉइस ट्रैफिक को कैरी करने के लिए ग्रे रूट के प्रति आकर्षण में कमी आएगी और इससे अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग ट्रैफिक के कैरियर रूट में उचित वृद्धि देखने को मिलेगी। तदनुसार, प्राधिकरण ने आईयूसी विनियम, 2018 के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में इस प्रकार टिप्पणी की है:
- "प्राधिकरण देश में आईएलडी वॉइस ट्रैफिक के रुझानों और स्वरूपों की बारीकी से निगरानी करेगा। यदि जरूरत पड़ी तो प्राधिकरण समय-समय पर आईटीसी की समीक्षा कर सकता है"।*

14. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण दूरसंचार बाजार के विकास और इनकमिंग एवं आउटगोइंग लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय (आईएलडी) वॉइस ट्रैफिक वॉल्यूम के रुझानों की लगातार निगरानी कर रहा है। इनकमिंग और आउटगोइंग आईएलडी वॉइस ट्रैफिक वॉल्यूम के रुझानों का समय-समय पर विश्लेषण करने के लिए, प्राधिकरण कैरियर रूट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग और आउटगोइंग वॉइस ट्रैफिक से संबंधित डेटा एकत्र करता रहा है। इस डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि 2018 में आईटीसी की दर की समीक्षा करने के बाद, कैरियर रूट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग वॉइस ट्रैफिक में गिरावट की दर कम हो गई है। जहां तक भारत से आउटगोइंग वॉइस ट्रैफिक का संबंध है, तो इनकमिंग आईएलडी वॉइस ट्रैफिक की तुलना में बहुत कम है। आउटगोइंग आईएलडी ट्रैफिक में केवल मामूली कमी देखी गई है। इसके अलावा, वैश्विक रुझान और भारत में डेटा-सक्षम ग्राहकों की संख्या में तेज वृद्धि की वजह से वॉइस कॉलिंग के लिए ओटीटी संचार अनुप्रयोगों का उपयोग बढ़ा है। चूंकि ओटीटी के अधिकांश संचार अनुप्रयोग वॉइस कॉल के लिए शुल्क नहीं लेते हैं, इसलिए ओटीटी वॉइस ट्रैफिक में वृद्धि ग्रे-मार्केट के ऑपरेशन को भी प्रभावित कर सकती है।
15. पिछले कुछ वर्षों में, यह भी देखा गया है कि दुनिया और भारत में दूरसंचार बाजार की संरचना, वॉइस से डेटा-केंद्रित बाजार में बदल गई है। ट्रिपल-प्ले ऑफरिंग (वीडियो, वॉइस और डेटा) जैसी सेवाओं के अभिसरण की प्रवृत्ति ने सेवा प्रदाताओं की मूल्य निर्धारण रणनीतियों में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके परिणामस्वरूप बंडलड टैरिफ का प्रचलन बढ़ा है। इस दौरान, भारत में, यह भी देखा गया है कि अधिकांश मोबाइल टैरिफ ऑफर बंडलड प्लान की तरफ चले गए हैं, यानी वे वॉइस कॉल मिनट, एसएमएस और डेटा को शामिल करते हैं। इसी तरह, अंतरराष्ट्रीय रोमिंग के मामले में, इनकमिंग और आउटगोइंग वॉइस कॉल, डेटा और संदेशों की तय पूर्व-निर्धारित मात्रा वाले बंडलों के रूप में टैरिफ पैकेज लोकप्रिय हो रहे हैं। टैरिफ ऑफरिंग में इन वृद्धियों के मद्देनजर, ऐसा लगता है कि खुदरा स्तर पर, व्यक्तिगत उत्पाद यानी वॉइस, डेटा और संदेश की प्रति यूनिट दरों की प्रासंगिकता कम हो रही है।
16. उपर्युक्त घटनाक्रम से प्रश्न उठता है कि क्या आईटीसी के लिए प्रति मिनट के आधार पर एक समान दर निर्धारित करने वाली वर्तमान विनियामक व्यवस्था अभी भी प्रासंगिक है या इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है? क्या भारतीय आईएलडीओ को अंतर्राष्ट्रीय कैरियर्स के साथ मोलभाव के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए? कैरियर-रूट ट्रैफिक और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ पर इन बदलावों के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? हितधारकों के साथ इन सभी मुद्दों और किसी अन्य प्रासंगिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, प्राधिकरण ने आईटीसी की मौजूदा विनियामक व्यवस्था की समीक्षा को जरूरी समझा है।
17. इस पृष्ठभूमि के आधार पर, प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 08.11.2019 को "इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। हितधारकों को अपनी लिखित टिप्पणी 09.12.2019 और प्रति-टिप्पणी 23.12.2019 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
18. कंपनियों, संगठनों, फर्मों और व्यक्तियों सहित टीएसपी, उद्योग संघों और अन्य हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर अपलोड की गईं। सभी हितधारकों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में 03.02.2020 को एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, प्राधिकरण द्वारा इस मुद्दे पर अब तक प्राप्त सभी टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों पर विचार किया गया है। परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर आईटीसी से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण और आगे के विचार-विमर्श को नीचे प्रस्तुत किया गया है।
- ड. परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणियों का विश्लेषण
19. दिनांक 08.11.2019 के परामर्श पत्र में, प्राधिकरण ने आईयूसी से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी थी:
- (प्र1): अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोनी बाजार संरचना में हो रहे बदलावों के दृष्टिगत, क्या अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार (आईटीसी) के लिए मौजूदा विनियामक व्यवस्था में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है, यानी मौजूदा विनियामक व्यवस्था को आईटीसी की समान दर से बदलकर वैकल्पिक दृष्टिकोण कर दिया जाए? कृपया अपनी टिप्पणी के समर्थन में तर्क देकर इसका औचित्य सिद्ध करें।
 - यदि प्र1 के लिए आपका जवाब हां में है, तो वैकल्पिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? कृपया वैकल्पिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करें और वर्तमान दृष्टिकोण की तुलना में इसके लाभों के बारे में बताएं।
 - यदि प्र1 के लिए आपका जवाब ना में है, तो अंतरराष्ट्रीय टेलीफोनी बाजार के बदलते परिदृश्य में, विनियामक द्वारा भारतीय उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा के लिए अन्य कौन से विनियामक उपाय किए जाने की आवश्यकता है? कृपया अपनी टिप्पणी के समर्थन में तर्क देकर इसका औचित्य सिद्ध करें।
 - आप अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार से संबंधित किसी अन्य मुद्दे पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कर सकते हैं।
20. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, अधिकांश हितधारक आईटीसी दर में वृद्धि के पक्ष में थे। उनके अनुसार, इससे भारतीय पहुंच सेवा प्रदाताओं को अपने ग्राहकों को अधिक किफायती आईएसडी टैरिफ प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी, देश को अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और सरकारी खजाने को अधिक राजस्व मिलेगा। हालांकि, जहां तक आईटीसी के लिए विनियामक व्यवस्था का प्रश्न है, इस पर हितधारक एकमत नहीं हैं। उनमें से कुछ ने समापन प्रभार में वृद्धि के साथ आईटीसी की स्थिर समान दर की मौजूदा विनियामक व्यवस्था को जारी रखने का समर्थन किया, जबकि अन्य ने वैकल्पिक विनियामक व्यवस्था का समर्थन किया, जैसे कि ऊपरी सीमा के साथ फोरबेयरंस में या एक निर्धारित सीमा के भीतर फोरबेयरंस में।

21. अधिकांश हितधारकों ने कहा कि आईटीसी दर को उसके वर्तमान स्तर यानी 0.30 रु. प्रति मिनट से बढ़ाया जाना चाहिए; वहीं कुछ हितधारकों ने तर्क दिया कि आईटीसी को कम करके घरेलू समापन प्रभार (डीटीसी) के स्तर पर लाया जाना चाहिए। उपभोक्ता संगठनों में से एक ने आईटीसी को पूरी तरह से समाप्त करने की भी वकालत की। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में डीटीसी निम्नानुसार है:

(क) वायरलेस से वायरलेस कॉल के लिए 0.06 रु. प्रति मिनट; और

(ख) वायरलाइन से वायरलेस, वायरलेस से वायरलाइन और वायरलाइन से वायरलाइन कॉल के लिए शून्य।

परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों का सारांश और उनका विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

I. मौजूदा विनियामक व्यवस्था की समीक्षा:

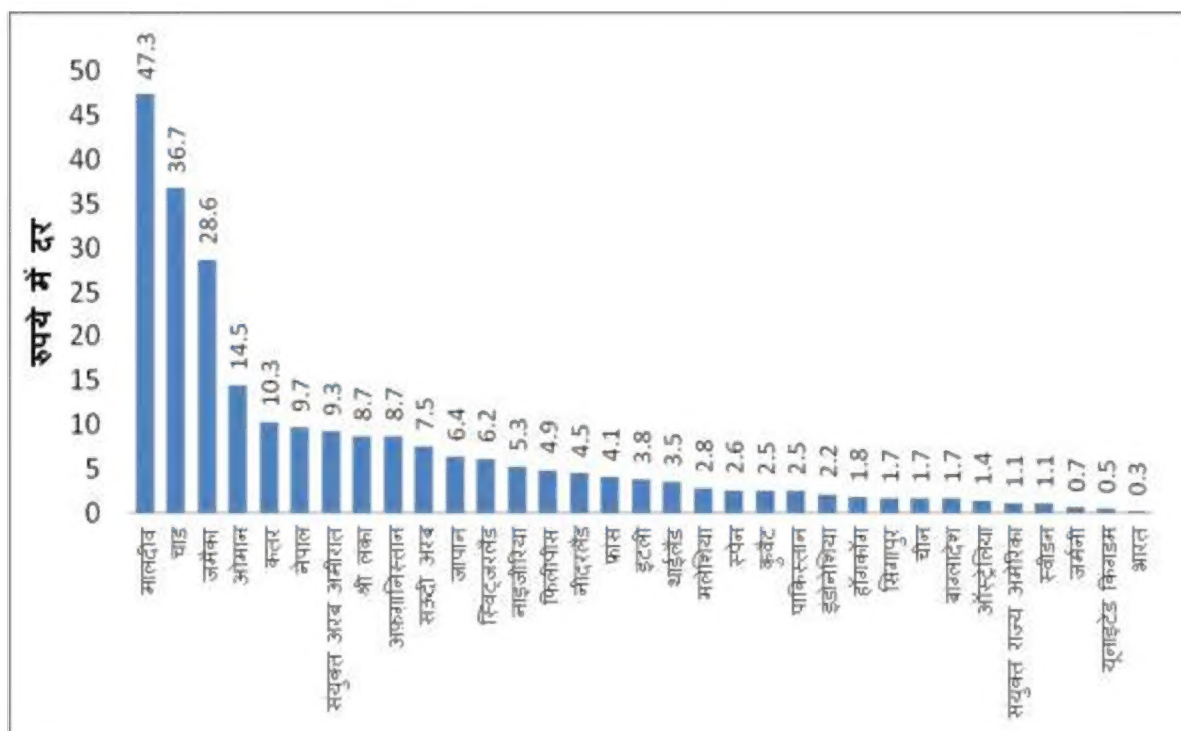
22. एक हितधारक के अनुसार, डेटा सेवाओं को अपनाने में भारी वृद्धि, बंडल टैरिफ प्लान्स की व्यापकता, ओटीटी पैठ में तेजी से वृद्धि, भारत से आउटगोइंग ट्रेफिक में गिरावट के उभरते रुझान के साथ कैरियर रूट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग वॉइस ट्रेफिक में गिरावट के रुझान को देखते हुए, यह समय आईटीसी की समीक्षा के लिए उपयुक्त है। इस हितधारक ने आगे कहा कि 2018 में आईटीसी में कमी के पीछे प्राधिकरण की अच्छी मंशा का अंतर्राष्ट्रीय ट्रेफिक वैल्यू चेन के विभिन्न हितधारकों द्वारा अनादर किया गया है। इस हितधारक के अनुसार, आईटीसी में 43% से अधिक की कमी का लाभ कमी भी विदेशी सेवा प्रदाताओं द्वारा अंतिम उपयोगकर्ताओं को नहीं दिया गया और आईटीसी दर में कमी के बावजूद भारत के लिए कॉल प्रभार स्थिर बने रहे या बढ़ गए थे।
23. कुछ हितधारक आईटीसी के लिए वैकल्पिक विनियामक व्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं जैसे कि फोरबेयरंस व्यवस्था या पारस्परिक समापन दर व्यवस्था। उनका मानना है कि आईटीसी दर को फोरबेयरंस में रखने से, एक सेवा प्रदाता को उच्च आईटीसी दरों को रखने के लिए आकर्षित किया जा सकता है, जो विदेशी कैरियर्स के साथ लंबे मोलभाव का कारण बन सकता है। इसी तरह, पारस्परिक समापन दर व्यवस्था के विकल्प में मूल्य-वृद्धि की होड़ लगने की संभावना है, जो अनुकूल समापन दर वाले देशों के माध्यम से ट्रेफिक के संचालन का कारण बन सकती है। इसलिए, वे मानते हैं कि नियत आईटीसी सबसे बेहतर व्यवस्था है। इन हितधारकों ने यह कहते हुए आईटीसी दर में वृद्धि की सिफारिश की है कि इसका प्रभाव भारतीय ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा और दूसरी ओर भारतीय ऑपरेटरों को अधिक विदेशी मुद्रा मिलेगी और परिणामस्वरूप सरकारी खजाने के राजस्व में वृद्धि होगी।
24. एक सरकारी स्वामित्वाधीन टीएसपी ने कहा कि आईयूसी का मूल्यांकन वास्तविक लागतों के आधार पर किया जाना चाहिए, और इस तरह की लागतों में एचआर लागतें भी शामिल की जानी चाहिए। समापन प्रभार के किसी भी पहलू को तय करते समय, भादूविप्रा को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नेटवर्क लागतों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि इनकमिंग और आउटगोइंग आईएलडी ट्रेफिक मिनटों में विभिन्न कारणों से लगातार कमी आ रही है, इसलिए आईटीसी में प्रत्यक्ष कमी के माध्यम से या अन्य तरीकों जैसे फोरबेयरंस के नियम को लागू करने से की गई अतिरिक्त कमी करने के परिणामस्वरूप और नेटवर्क लागत के वसूल नहीं होने के कारण टीएसपी को होने वाली हानि बढ़ जाएगी। इस हितधारक ने अनुरोध किया है कि आईएलडी समापन प्रभार के लिए वर्तमान विनियामक प्रावधानों को जारी रखा जा सकता है। बहरहाल, यदि आवश्यक हो तो एक सीमा में ट्रेफिक-वॉल्यूम स्लैब आधारित आईएलडी समापन प्रभार की दरें तय की जा सकती हैं।
25. एक टीएसपी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोनी संरचना के ओटीटी की ओर शिफ्ट करने से नियत समान दृष्टिकोण से वैकल्पिक दृष्टिकोण की ओर शिफ्ट किए जाने की आवश्यकता भी हो सकती है। इस टीएसपी के अनुसार, आईटीसी में इस तरह के दृष्टिकोण को एक निर्धारित सीमा के भीतर फोरबेयरंस में रखा जाना चाहिए। उक्त टीएसपी के अनुसार, इस तरह की निर्धारित सीमा, न्यूनतम अर्थात् 0.75 रु. से 1.25 रु. होनी चाहिए।
26. ऐसी ही राय रखने वाले एक हितधारक ने कहा कि इस सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा अधिक है और कई कारक हैं जो विनियामक के नियंत्रण में नहीं हैं जिनमें ओटीटी की चुनौतियां शामिल हैं। इस परिदृश्य में, भादूविप्रा द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के साथ फोरबेयरंस में रखने का विकल्प, टीएसपी को संवाद करने और ओटीटी की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक शक्ति देगा। उनके विचार में, टीएसपी हमारे देश में या अन्य देशों के टीएसपी के साथ वॉल्यूम आधारित या प्लैट-रेट प्रभार पर भी मोलभाव कर सकते हैं। इसने भारत में आने वाली अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल के लिए आईटीसी को फोरबेयरंस में रखने का भी सुझाव दिया है, क्योंकि यह कई देशों में अपनाया जाता है और भारत में आउटगोइंग अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल के मामले में भी। विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय कैरिज प्रभार और अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार भी फोरबेयरंस में रखे गए हैं।
27. एक अन्य हितधारक ने कहा है कि आईटीसी को कम करके ग्रे मार्केट पर अंकुश लगाने और कैरियर रूट पर ट्रेफिक को बढ़ाने की रणनीति को सीमित सफलता मिली है। उसने तर्क दिया कि एक अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉल के लिए, एक विनियमित दर के माध्यम से या फोरबेयरंस में रखने की व्यवस्था के मामले में, दर को घरेलू रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए न कि विदेशी पहुंच प्रदाता (एफएपी) द्वारा। फोरबेयरंस में रखने की व्यवस्था के मामले में, सेवा प्रदाताओं के अप्रत्याशित व्यवहार के जोखिमों और आईटीसी में अभूतपूर्व बदलाव से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करने से सुरक्षा देने के लिए आईटीसी के लिए उच्चतम दर के साथ फोरबेयरंस के दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है।
28. उपर्युक्त बिंदुओं से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश हितधारकों ने आईटीसी की समीक्षा के लिए सुझाव दिया है, जबकि आईटीसी के लिए विनियामक व्यवस्था के संबंध में उनकी राय अलग-अलग है। कुछ हितधारकों ने समान आईटीसी दर की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का सुझाव दिया है, कई अन्य हितधारकों ने वैकल्पिक दृष्टिकोण का सुझाव दिया है। मोटे तौर पर, हितधारकों ने निम्नलिखित पांच दृष्टिकोणों के बारे में टिप्पणी की है, जैसे

- (क) नियत समान आईटीसी की मौजूदा विनियामक व्यवस्था को जारी रखना;
- (ख) आईटीसी को पूरी तरह से फोरबेयरंस में रखना;
- (ग) पारस्परिक आईटीसी दरों को रखना अर्थात् भारत और विदेश में आईटीसी की एक ही दर रखना;
- (घ) आईटीसी को उच्चतम सीमा के साथ फोरबेयरंस में रखना; और
- (ङ) पूर्व निर्धारित सीमा के भीतर आईटीसी को फोरबेयरंस में रखना।
29. प्राधिकरण इस बात से अवगत है कि कोई भी इनकमिंग कॉल (अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग कॉल सहित) कॉल्ल पार्टी के पहुंच सेवा प्रदाता (यानी वो पहुंच सेवा प्रदाता, जिसका ग्राहक इनकमिंग कॉल प्राप्त करता है) का एकाधिकार है। यदि आईटीसी पूर्ण फोरबेयरंस के अधीन है, तो कॉल्ल पार्टी का पहुंच सेवा प्रदाता आईएलडीओ से अधिक से अधिक समापन प्रभार लेने का प्रयास कर सकता है। यह प्रभार आईएलडीओ द्वारा एफएपी से लिया जाएगा। एक निश्चित सीमा से परे, एफएपी आईटीसी की दर में ऐसी वृद्धि को भारत-बाउंड आउटगोइंग आईएलडी कॉल के टैरिफ को बढ़ाकर अपने ग्राहकों को हस्तांतरित कर सकते हैं। इससे कैरियर रूट से ओटीटी रूट में आईएलडी ट्रैफिक को शिफ्ट करने में तेजी आ सकती है। इसलिए, आईटीसी की दर में बेतहाशा वृद्धि से किसी भी हितधारक का भला नहीं हो सकता है। तदनुसार, इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से खारिज किया जाता है।
30. जहां तक पारस्परिक आईटीसी दर दृष्टिकोण का संबंध है, हितधारकों ने इस दृष्टिकोण के खिलाफ कारण गिनाए हैं। इस व्यवस्था में मूल्य-वृद्धि की होड़ बढ़ने की संभावना है, जिससे बाद में, अनुकूल समापन दर वाले देशों के माध्यम से ट्रैफिक रूटिंग हो सकती है। ऐसे मामलों में, ओरिजिनेटिंग कॉल लोकेशन की पहचान छिपी रहती है, जिससे कॉलिंग लाइन पहचान (सीएलआई) का मिथ्याकरण होगा, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। तदनुसार, प्राधिकरण का मानना है कि यह दृष्टिकोण आईएलडी बाजार में अधिक अनिश्चितता और व्यवधान पैदा कर सकता है। इसलिए इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से खारिज किया जाता है।
31. जहां तक निश्चित एकसमान आईटीसी के मौजूदा विनियामक व्यवस्था का संबंध है, हालांकि यह ऑपरेशन्स में सुगमता सुनिश्चित करता है, परंतु यह तेजी से बदलते आईएलडी बाजार में सेवा प्रदाताओं के लिए आवश्यक लचीलेपन को प्रतिबंधित करता है। आईटीसी की पूर्व-निर्धारित दर की वजह से भारतीय ऑपरेटर विदेशों में अपने विदेशी समकक्षों के साथ समापन दरों पर मोलभाव करने में सक्षम नहीं हैं, जो फिलहाल फोरबेयरंस के अधीन है। इसके अलावा, निर्धारित समान आईटीसी दृष्टिकोण के लिए प्राधिकरण के लगातार हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके अंतर्निहित कारक जैसे विदेशी मुद्रा दरें, ट्रैफिक पैटर्न, विदेशी एंड पर समापन प्रभार आदि में खुले बाजार में बदलाव होते रहते हैं। यह व्यवस्था उस समय अधिक उपयुक्त थी, जब अधिकांश आईएलडी ट्रैफिक केवल कैरियर रूट से संचालित होता था। अब, नई प्रौद्योगिकियों के आने से, जब ओटीटी रूट आईएलडी वॉइस कॉल के लिए एक विकल्प के रूप में सामने आया है, तो प्राधिकरण का भी मानना है कि आईटीसी की दर तय करने में सेवा प्रदाताओं के लिए कुछ लचीलापन देना दूरसंचार क्षेत्र के हित में होगा। सेवा प्रदाता इस लचीलेपन का उपयोग आईटीसी की इष्टतम दर की खोज के लिए कर सकते हैं, जो न केवल कैरियर रूट के माध्यम से ट्रैफिक को बढ़ाने में मदद करता है, जोकि उनके हित में है, बल्कि ग्रे-मार्केट ऑपरेशन्स को भी हतोत्साहित करता है।
32. उपरोक्त पैरा 28 में आईटीसी की दर तय करने के लिए पहले तीन विकल्पों को चर्चा के बाद खारिज कर दिया गया है, शेष विकल्प उच्चतम सीमा के साथ फोरबेयरंस और पूर्व-निर्धारित सीमा के अंदर फोरबेयरंस के हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, चूंकि इनकमिंग आईएलडी ट्रैफिक आउटगोइंग आईएलडी ट्रैफिक से बहुत अधिक है, इसलिए आईटीसी भारतीय टीएसपी के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए, यह आवश्यक है कि आईटीसी के लिए कोई वैकल्पिक विनियामक व्यवस्था तय करते समय, विनियामक निश्चितता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक खुले बाजार में, जहां बाजार सहभागियों का आकार काफी अलग होता है, मोलभाव की शक्ति भी अलग-अलग होती है। विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियों में भी ऐसा ही प्रदर्शित होता है। इस समय, उच्चतम सीमा के साथ फोरबेयरंस में रखने के विकल्प को चुनने से राजस्व के इस महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में अनिश्चितता पैदा हो सकती है, खासकर छोटे ऑपरेटरों को। यदि ऐसे ऑपरेटर बेहतर दरों पर मोलभाव करने में सक्षम नहीं हैं, तो इस स्रोत से उनका मौजूदा राजस्व भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए, प्राधिकरण की राय में, इस समय, जब हम निश्चित समान आईटीसी व्यवस्था से शिफ्ट कर रहे हैं, तो पूर्व-निर्धारित सीमा के भीतर फोरबेयरंस में रखना ही एक बेहतर विकल्प होगा। काफी हद तक, यह ऐसे हितधारकों की चिंताओं का भी निवारण करेगा जो निश्चित समान आईटीसी व्यवस्था को जारी रखने की वकालत कर रहे हैं क्योंकि यह निकटतम वैकल्पिक दृष्टिकोण है, जो सेवा प्रदाताओं को बाजार में उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक लचीलापन भी प्रदान करता है। सेवा प्रदाताओं को प्रदान किया गया ऐसा लचीलापन उन्हें अपने ग्राहकों के हित में नए टैरिफ मॉडल तैयार करने में मदद कर सकता है।
33. वर्तमान में, भारत में आईएलडी वॉइस टेलीफोनी बाजार में, हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार के आईएलडीओ हैं। पहले वे हैं, जो केवल आईएलडी स्पेस में काम करते हैं, और दूसरे वे हैं, जो पहुंच सेवा के साथ-साथ आईएलडी स्पेस में काम करते हैं। आईटीसी के लिए संशोधित विनियामक व्यवस्था अर्थात् पूर्व-निर्धारित सीमा के भीतर फोरबेयरंस में, सेवा प्रदाताओं, जिनके पास आईएलडीओ ऑपरेशन्स भी हैं, को एकल आईएलडीओ को पारदर्शी और पक्षपातहीन तरीके से मैचिंग समापन दरों को पेश करना आवश्यक होगा। इस मद में किसी भी प्रकार के भेदभाव की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि आवश्यक समझा गया, तो भाद्विप्रा अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त जांच शुरू की जा सकती है और परिणामी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

II. आईटीसी की दर

34. कुछ हितधारकों का मानना था कि भारत में 0.30 रु. प्रति मिनट आईटीसी की दर शायद दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि, यहां तक कि पड़ोसी सार्क देशों जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की औसत मिश्रित आईटीसी दर लगभग 4 रु. से 6.50 रु. प्रति मिनट है। जबकि मध्य पूर्व में औसत मिश्रित आईटीसी की दर 8 से 9 रु. प्रति मिनट है। इन हितधारकों के अनुसार, केवल कुछ देशों के पास आईटीसी की तुलनात्मक दरें हैं, हालांकि ये अभी भी भारत की तुलना में बहुत अधिक हैं। इन हितधारकों ने अपने तर्कों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार दरों के निम्नलिखित वैश्विक रुझान का सहारा लिया है:

चित्र 1: वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार दरें



स्रोत: एक टीएसपी द्वारा अपनी टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत

- अतः, इन हितधारकों के अनुसार, भारतीय ऑपरेटर भारत से आने वाली कॉल की समाप्ति के लिए विदेशी पहुंच प्रदाता (एफएपी) को औसतन 3.0 से 3.50 रु. प्रति मिनट का भुगतान करते हैं और भादूविप्रा ने भारतीय पहुंच प्रदाताओं के लिए 0.30 रु. प्रति मिनट आईटीसी तय किया है जो दुनिया के औसत के 10 प्रतिशत से भी कम है।
35. एक टीएसपी ने तर्क दिया कि प्राधिकरण ने आईटीसी दर 0.53 रु. प्रति मिनट से घटाकर 0.30 रु. प्रति मिनट करते समय, ग्रे रूट पर अंकुश लगाने को सबसे महत्वपूर्ण विनियामक प्राथमिकता माना था ताकि कैरियर रूट के माध्यम से समाप्त होने वाले भारतीय ट्रैफिक में बढोतरी हो। लेकिन, आईएलडी समापन प्रभार में इस कमी के बावजूद, कैरियर रूट के माध्यम से आईएलडी इनकमिंग मिनटों में अधिक तेजी से गिरावट जारी है।
36. एक अन्य टीएसपी ने तर्क दिया कि कई देशों में एफएपी के पास अंतरराष्ट्रीय कैरियर्स के साथ व्यावसायिक मोलभाव से तय किए हुए दर हैं। इस टीएसपी के अनुसार, भारत से भारतीय आईएलडीओ को आउटबाउंड कॉल की लागत बहुत अधिक है और इनमें से अधिकांश लागत एफएपी द्वारा अपने नेटवर्क पर समाप्त कॉल के लिए प्रभारित की जाती है। एफएपी आरंभ और समापन दोनों के लिए भारतीय पहुंच ऑपरेटरों से कई गुना अधिक कमा रहे हैं। तदनुसार, इस टीएसपी के अनुसार, आईटीसी की दर में वृद्धि करना उचित है जो सीपी में निर्धारित मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगा।
37. एक हितधारक के अनुसार, पिछली समीक्षा के बाद से दो वर्षों की अवधि में, यूरोप, अफ्रीका, एशिया-प्रशांत आदि में टेलीकॉम कंपनियों द्वारा आईटीसी में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय पहुंच सेवा प्रदाताओं द्वारा अधिक भुगतान किया गया है और भारतीय ग्राहकों से आईएसडी टैरिफ के रूप में अधिक दरें प्रभारित की गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि कम समापन प्रभार भारतीय टीएसपी

- के लिए समानता सुनिश्चित नहीं करता है। तदनुसार, इस हितधारक के अनुसार, विदेशी ऑपरेटरों को भुगतान की जाने वाली आईएलडी लागत में वृद्धि और ग्राहकों से आईएलडी राजस्व में कमी का ऑपरेटरों पर समग्र प्रभाव बेहद नकारात्मक रहा है।
38. कुछ हितधारकों ने तर्क दिया कि विश्व औसत से कम आईटीसी दर की वजह से भारतीय पहुंच प्रदाताओं का राजस्व उनके विदेशी समकक्षों की तुलना में कम है। इस तर्क के समर्थन में, एक टीएसपी ने कहा कि वित्त वर्ष 2016-2017 में आईटीसी की दर 0.53 रु. प्रति मिनट थी और आईटीसी की मद में विदेशी ऑपरेटरों से प्राप्य राशियों और आउटगोइंग अंतर्राष्ट्रीय कॉल के लिए विदेशी ऑपरेटरों को देय के आधार पर देश के लिए शुद्ध विदेशी मुद्रा का अर्जन 3675 करोड़ रु. था। इस टीएसपी के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-2019 में, देश के लिए शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन घटकर 950 करोड़ रु. हो गया था, जिसके कारण विदेशी मुद्रा लाभ में लगभग 75 प्रतिशत की कमी आई है। इसलिए, इन हितधारकों के अनुसार, आईटीसी दर में कमी से विदेशी मुद्रा के मामले में सरकार और राष्ट्र को काफी घाटा उठाना पड़ा है।
39. एक सेवा प्रदाता के अनुसार, चूंकि अलग-अलग देश अलग-अलग आईएससी प्रभारित करते हैं, इसलिए भारत के लिए इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय कॉल के लिए समापन प्रभार क्षेत्र/देश के साथ अलग-अलग रहते हुए फोरबेयरस में रखे जाने चाहिए। लेकिन ओरिजन-आधारित आईटीसी को लागू करना एक चुनौती हो सकती है क्योंकि विभिन्न एग्रीगेटर्स/विदेशी आईएलडीओ द्वारा हब्स के माध्यम से कॉल्स ट्रांसमिट की जा रही हैं। उसी के मद्देनजर, इस सेवा प्रदाता ने सिफारिश की है कि आईटीसी को तत्काल प्रभाव से 1 रु. प्रति मिनट और बाद में 3 से 3.50 रु. प्रति मिनट किया जाना चाहिए, अर्थात् भारतीय पहुंच सेवा प्रदाताओं द्वारा विदेशों में आईएलडी कॉल की समाप्ति के लिए दिए गए प्रभार के बराबर।
40. अधिकांश टीएसपी का यह मानना है कि ग्रे-मार्केट की चिंताओं के कारण आईटीसी में कमी की आवश्यकता नहीं है। एक टीएसपी ने तर्क दिया है कि ग्राहक के कड़े सत्यापन, ऑपरेटरों द्वारा किए गए विधिवत विश्लेषण और दूरसंचार विभाग के एलएसए (लाइसेंस सेवा क्षेत्र) यूनिटों को नियमित रिपोर्टिंग द्वारा ग्रे-मार्केट की चिंताओं को पहले से ही समाधान किया जा रहा है। उनके विचार में, जहां तक ग्रे मार्केट से संबंधित सुरक्षा मुद्दों का सवाल है, लागत उन लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है जो इस चैनल का फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए, इन हितधारकों के अनुसार, आर्बिट्राज को कम करके, हम सुरक्षा आवश्यकताओं को नरजंदाज करने के इरादे से विशेष रूप से सेटअप ग्रे-मार्केट ऑपरेशन को समाप्त नहीं कर सकते हैं।
41. कुछ हितधारक इस विचार के हैं कि, आईएलडी कॉल के संबंध में, कैरियर से ओटीटी रूट में प्रतिस्थापन वैश्विक संदर्भ में कम नहीं हो रहा है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में कैरियर मार्ग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वॉइस ट्रैफिक में निरंतर कमी और ओटीटी मार्ग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वॉइस ट्रैफिक में निरंतर वृद्धि देखी गई है। इस तर्क के समर्थन में, एक टीएसपी ने कैरियर बनाम ओटीटी मार्ग के माध्यम से किए गए अनुमानित ट्रैफिक (बिलियन मिनटों में) की एक साल-दर-साल की तुलना प्रदान की है, जिसे तालिका-1 में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1: कैरियर बनाम ओटीटी रूट के माध्यम से संचालित कुल ट्रैफिक बिलियन मिनट

वर्ष	कैरियर ट्रैफिक	ओटीटी ट्रैफिक	कैरियर ट्रैफिक में % वृद्धि	ओटीटी ट्रैफिक में % वृद्धि
2015	553.3	418.5		
2016	527.9	570.3	-4.6%	36.3%
2017	483.8	757.2	-8.4%	32.8%
2018*	449.9	952.4	-7.0%	25.8%

*2018 के आंकड़े अनुमानित हैं

स्रोत: 'द स्टेट ऑफ द नेटवर्क' का टेलीजियोग्राफी 2019 संस्करण

इस रिपोर्ट के अनुसार, कैरियर रूट के माध्यम से इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय वॉइस ट्रैफिक में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसी ही राय रखने वाले एक अन्य टीएसपी का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग के लिए ओटीटी में वृद्धि एक वैश्विक घटना है, इसने विदेशों में ऑपरेटरों को अपनी समापन दर को कम करने के लिए विवश नहीं किया है। इस टीएसपी के अनुसार, इस समस्या का समाधान ओटीटी कंपनियों को विनियमित करने में निहित है, न कि अपने वैध राजस्व को तहस-नहस करने में।

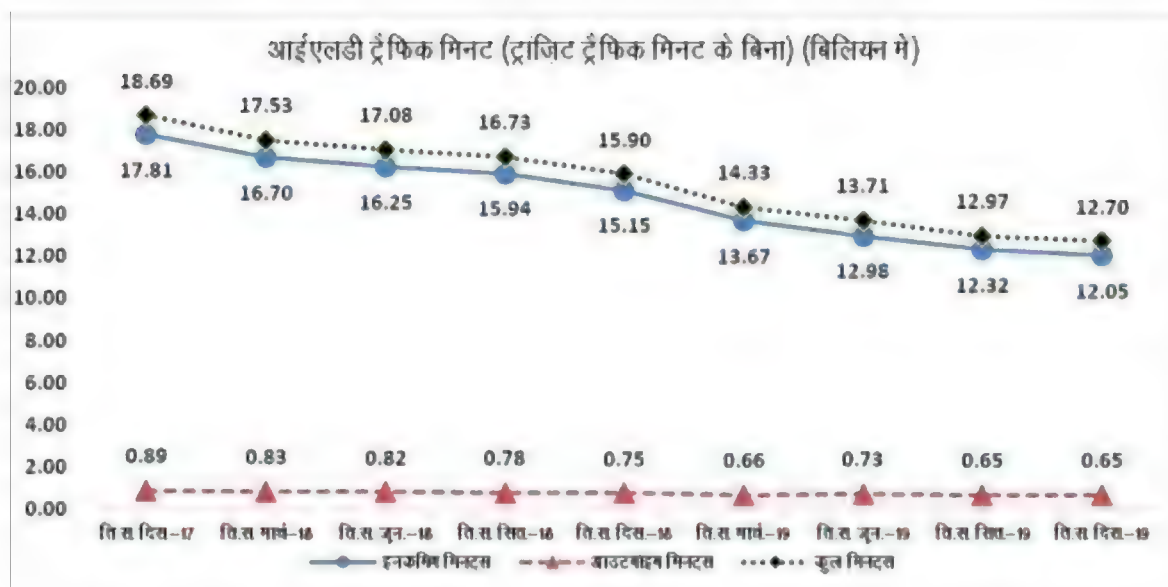
42. एक और टीएसपी ने नियत आईटीसी की मौजूदा विनियामक व्यवस्था को जारी रखने का समर्थन किया और प्रस्ताव किया कि दूरसंचार के क्षेत्र में विभिन्न बदलावों को देखते हुए आईटीसी को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए और इसे बढ़ाकर 0.65 से 0.75 रु. प्रति मिनट किया जाना चाहिए। इस टीएसपी के अनुसार, विदेशी ऑपरेटरों ने आईटीसी में प्रति मिनट 23 पैसे की कमी के लाभों को अपने ग्राहकों को नहीं दिया है और केवल अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाया है।
43. एक अन्य सेवा प्रदाता ने कहा कि कई देशों में समापन प्रभार भारत में आईटीसी की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक है और 2015 से 2019 तक डॉलर की विनिमय दर भिन्नता 62 से 71 रु. है और भारतीय आईएलडीओ अकाउंट के सेटलमेंट के लिए विदेशी कैरियर्स को यूएस डॉलर में अंतर्राष्ट्रीय सेटलमेंट प्रभार (आईएससी) का भुगतान करते हैं। इस सेवा प्रदाता का मानना है कि इनकमिंग समापन दर, जो वर्तमान में भारत में 0.30 रु. प्रति मिनट है, यूएस. सेंट के संदर्भ में 1 सेंट/मिनट तय की जाए, जो इनकमिंग आईयूसी की कटौती में विदेशी मुद्रा भिन्नता के संबंध में राहत प्रदान करेगा। इस टीएसपी ने यह भी सलाह दी है कि देश में आईटीसी को सभी समापन नेटवर्क के लिए एक समान रखा जा सकता है।
44. इसी तरह की राय रखने वाली एक कंसल्टिंग फर्म के अनुसार, दुनिया के कई देशों में, जहां पर आईएलडी ट्रैफिक का एक महत्वपूर्ण वॉल्यूम है, समापन प्रभार फोरबेयरस में रखे गए हैं और टीएसपी द्वारा मोलभाव के अनुसार तय किए जाते हैं। चूंकि भारत में समापन प्रभार एक समान दर पर तय किए गए हैं, एफएपी ने तुलनात्मक रूप से अपनी उच्च दरों के साथ इस स्थिति का लाभ उठाया है और वे अपने बाजारों में व्यावहारिक रूप से मूल्य निर्माता बन गए हैं। इस हितधारक के अनुसार, भारतीय आईएलडीओ विदेशी ऑपरेटरों से प्रति मिनट कम राजस्व कमा रहे हैं, जब भारतीय आईएलडीओ द्वारा विदेशी ऑपरेटरों को भुगतान किए गए प्रति मिनट की लागत की तुलना की जाती है। उनकी राय में, भारतीय बाजारों को समान दर जारी रखनी चाहिए, जो कम सेटलमेंट दर वाले देशों के माध्यम से कॉल की रि-रूटिंग कम या समाप्त कर सकते हैं और समापन प्रभार बढ़ाना चाहिए। उन्होंने इस तर्क के आधार पर आईटीसी को बढ़ाकर कम से कम 0.60 या 0.70 रु. प्रति मिनट करने का सुझाव दिया है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर \$ 0.5 की अनुमानित राशि का भुगतान किया जा रहा है।
45. भारतीय बाजार में काम कर रहे एकल आईएलडीओ के अनुसार, उन्हें कम राजस्व मार्जिन के कारण जीविका की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लंबे भुगतान चक्रों का खामियाजा भुगतान पड़ रहा है। उनके अनुसार, सरकार और विनियामक उन एएसपी की मदद कर रहे हैं जो कम मार्जिन का सामना कर रहे हैं। इसी तरह की मदद की जरूरत विशेष रूप से उन आईएलडीओ को है जिनकी पहुंच बड़े कैपिटल एक्सेस नेटवर्क तक नहीं है। उन्होंने अनुरोध किया है कि ट्रैफिक असंतुलन, ग्रे मार्केट ऑपरेशन और ओटीटी अनुप्रयोगों के लिए ट्रैफिक शिफ्टिंग के मुद्दों के अलावा, आईटीसी पर व्यवस्था के लिए कोई भी निर्णय लेते समय एकल आईएलडीओ के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे ही एक ऑपरेटर ने सुझाव दिया है कि डीटीसी से ऊपर के किसी भी विभेदक प्रभार को आईएलडीओ और एएसपी के बीच 60:40 के अनुपात में वितरण को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस ऑपरेटर के अनुसार, यदि भादूविप्रा द्वारा इस तरह के अंतर राजस्व का वितरण अनिवार्य नहीं किया जाता है, तो यह अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक में वर्टिकल स्क्वीज का कारण बनेगा। उनकी राय में, इसका मतलब होगा कि एकल आईएलडीओ एकीकृत सेवा प्रदाताओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। इस हितधारक ने यह भी सुझाव दिया कि प्राधिकरण को ऐसे देशों के बीच आईटीसी के लिए कम पारस्परिक व्यवस्था करने के लिए प्रमुख ट्रैफिक विनिमय देशों में विनियामकों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क करना चाहिए। इससे भारतीय ग्राहकों के लिए आउटगोइंग आईएलडी कॉल की लागत को कम करने और ओटीटी से पीएसटीएन में ट्रैफिक को वापस शिफ्ट करने में भी मदद मिलेगी।
46. एक अन्य एकल आईएलडीओ ने तर्क दिया है कि आईयूसी का फ्रेमवर्क "वर्क डन" के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। उनकी नजर में, वर्तमान बाजार की स्थिति स्वतंत्र आईएलडीओ को बने रहने के लिए अनुपयुक्त बना रही है। इस आईएलडीओ के अनुसार, कुछ कैरियर्स द्वारा भारत में समापन हेतु दी जा रही बाजार कीमत, जो 0.48 अमेरिकी सेंट (0.345 रु.) है, काफी कम है, जो कि वर्तमान आईटीसी की दर 0.30 रु. होने के कारण आईएलडीओ के लिए केवल 4.5 पैसे का मामूली मार्जिन छोड़ता है। ये सेटलमेंट दर अरक्षणीय हैं। उनकी नजर में, आईएलडीओ को मिल रहा मार्जिन कॉल्स की कैरिज के लिए उनके द्वारा मैटेन किए

- जा रहे बैंडविड्थ की लागत तक को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि निवेश पर सही प्रतिफल मिल पाना तो दूर की बात है। इस हितधारक ने भारत से आउटगोइंग आईएलडी कॉल के कैरिज और भारत के लिए इनकमिंग कॉल के विभिन्न चरणों में शामिल उपकरणों और अवसंरचना के बारे में विस्तार से बताया है। इस आईएलडीओ के अनुसार, उन्हें दूरसंचार विभाग और प्राधिकरण द्वारा जारी नियामक निर्देशों का पालन करने के लिए कॉल की रूटिंग, बिलिंग और सेटलमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम के प्रबंधन के लिए अवसंरचना संपत्ति में बड़ा निवेश करने की आवश्यकता है। उन्होंने पहुंच और मोबाइल ऑपरेटरों को देय आईटीसी प्रभार की वर्तमान दर यानी 0.30 रु. को बनाए रखने और उनके निवेश प्रयासों के लिए आईएलडीओ के लिए अतिरिक्त 0.24 रु. आवंटित करने की सिफारिश की है।
47. आईटीसी में कमी का समर्थन करने वाले एक हितधारक ने कहा है कि एसपी द्वारा कॉल को समाप्त करने के लिए किया गया काम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कॉल के लिए समान है। उनकी दृष्टि में, आईटीसी को दो चरणों में घरेलू समापन प्रभार (डीटीसी) के बराबर लाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पहले चरण में आईटीसी को घटाकर 15 पैसे प्रति मिनट किया जा सकता है और दूसरे चरण में इसे डीटीसी के बराबर किया जा सकता है। उनकी राय में, यह ओटीटी कॉलिंग को हतोत्साहित करने में मदद करेगा, जिससे सुरक्षा की चिंता समाप्त होगी और अंततः ऑपरेटरों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
48. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश हितधारकों ने आईटीसी की दर में वृद्धि का सुझाव दिया है, संशोधित दर के संबंध में उनकी राय अलग-अलग है। जबकि एक हितधारक ने आईटीसी की दर को 3.5 रु. तक बढ़ाने का सुझाव दिया है, उनमें से ज्यादातर ने आईटीसी की दर को बढ़ाकर 0.75 रु. प्रति मिनट करने का सुझाव दिया है। एक अन्य हितधारक ने आईटीसी दर को 0.75 से 1.25 रु. प्रति मिनट करने का सुझाव दिया है। उनमें से कुछ ने आईटीसी की दर में वृद्धि के अनुरोध के साथ, यह भी सुझाव दिया है कि बढ़ी हुई राशि को आईएलडीओ के लिए रखा जाए न कि पहुंच सेवा प्रदाताओं के लिए। एक हितधारक ने आईटीसी की दर को डीटीसी के स्तर तक कम करने के लिए सुझाव दिया है।
49. इससे पहले कि हम आईटीसी की दर को डीटीसी के स्तर तक कम करने के प्रस्ताव की जाँच करें, यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि 01.02.2004 से 31.03.2009 तक की अवधि के लिए, प्राधिकरण ने आईटीसी को डीटीसी के बराबर निर्धारित किया था। बहरहाल, 01.04.2009 से, आईटीसी को डीटीसी की तुलना में एक उच्च स्तर पर निर्धारित किया गया था, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:
- क. 01.04.2009 से 28.02.2015 तक के लिए आईटीसी 0.40 रु. प्रति मिनट निर्धारित किया गया था जबकि डीटीसी 0.20 रु. प्रति मिनट था।
- ख. 01.03.2015 से 31.01.2018 तक के लिए आईटीसी 0.53 रु. प्रति मिनट निर्धारित किया गया था जबकि डीटीसी 0.14/0.06 रु. प्रति मिनट था।
- ग. 01.02.2018 से वर्तमान तिथि तक के लिए आईटीसी 0.30 रु. प्रति मिनट निर्धारित किया गया है जबकि डीटीसी 0.06 रु. प्रति मिनट है।
50. दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम, 2009 के माध्यम से पहली बार आईटीसी और डीटीसी के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित करते हुए प्राधिकरण ने कहा था कि लागतों का उन्मुखीकरण आईटीसी को तय करने का एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित अंतराष्ट्रीय समापन प्रभार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि भारतीय ऑपरेटरों और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए क्या अधिक फायदेमंद है। तत्पश्चात, जब प्राधिकरण ने दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2015 के माध्यम से आईटीसी और डीटीसी के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित कीं, तो यह कहा था कि आईटीसी को एक ऐसे स्तर पर तय किया जाना चाहिए जो तीन उद्देश्यों को पूरा करती हों यथा (क) आउटगोइंग इंटरनेशनल कॉल पर टैरिफ को कम करने और कॉलिंग कार्ड विनियम से उत्पन्न होने वाली राजस्व हानि को घरेलू टैरिफ तक जाने से रोकने के लिए टीएसपी को बढ़ावा देना; (ख) स्काइप, वाइबर जैसे ओटीटी हितधारकों के लिए ट्रैफिक के डायवर्जन को रोकना; और ग्रे मार्केट के लिए आर्बिट्राज अवसर नहीं बनाना, (ग) विदेशी विनियम दर भिन्नता के

प्रभाव को निष्प्रभावी बनाना। 2018 में, प्राधिकरण द्वारा आईटीसी की दर को संशोधित करके 0.30 रु. प्रति मिनट करते हुए भी इन सभी कारकों को ध्यान में रखा गया था।

51. प्राधिकरण का मानना है कि ये कारक अभी भी अपनी प्रासंगिकता कायम रखे हुए हैं। इसलिए, यह तर्क उचित नहीं है कि केवल वर्क डन सिद्धांत के आधार पर आईटीसी की दर तय की जानी चाहिए। इसके अलावा, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जब 2018 में आईटीसी की दर को 0.53 रु. से घटाकर 0.30 रु. करने से ओटीटी रूट के माध्यम इनकमिंग आईएलडी ट्रैफिक कम नहीं हुआ तो आईटीसी को डीटीसी के स्तर तक लाने से, कैसे ओटीटी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान हो जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। इस उपाय का सुझाव देने वाला हितधारक सहायक डेटा के साथ कोई तर्कसंगत कारण देने में विफल रहा है। वास्तव में, अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग के लिए ओटीटी ट्रैफिक में वृद्धि एक वैश्विक घटना है और अधिकांश अन्य देशों ने अपने डीटीसी के स्तर तक अपने अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार को कम नहीं किया है।
52. प्राधिकरण ने समय-समय पर आईएलडी ऑपरेटरों से इनकमिंग और आउटगोइंग आईएलडी ट्रैफिक से संबंधित आंकड़े एकत्र किए हैं। जिसके आधार पर, एक तिमाही आधार पर आईएलडी ट्रैफिक मिनट चित्र 2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

चित्र 2: आईएलडी ट्रैफिक मिनट (बिलियन में)



चित्र 2 से, यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि भारत से इनकमिंग और आउटगोइंग आईएलडी ट्रैफिक पिछले दो वर्षों के दौरान, अलग-अलग गति से कम हुए हैं, और इनकमिंग एवं आउटगोइंग आईएलडी मिनटों के बीच असंतुलन अभी भी काफी अधिक है और यह 18:1 पर है अर्थात् भारत में इनकमिंग आईएलडी मिनट भारत से आउटगोइंग आईएलडी मिनट से 18 गुना अधिक हैं। इसके अलावा, जैसा कि पहले बताया गया है, भारतीय ऑपरेटरों की आउटगोइंग आईएलडी कॉल के लिए समापन प्रभार के लिए प्रति मिनट लागत, प्रति मिनट आधार पर विदेशी ऑपरेटरों द्वारा भुगतान किए गए समापन प्रभार से उन्हें प्राप्त होने वाले राजस्व की तुलना में बहुत अधिक है। आईएलडीओ किसी भी देश की उच्च समापन दर का भार भारतीय पहुंच प्रदाताओं पर डालते हैं, जिससे भारतीय ग्राहकों को आईएसडी की सस्ती दर प्रदान करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। आईटीसी की दर में वृद्धि से मूल्य निर्धारण आर्बिट्राज को कम करने में मदद मिलेगी जो वर्तमान में विदेशी ऑपरेटरों के पक्ष में है। हालांकि, आईटीसी की दर में किसी भी वृद्धि पर विचार करते हुए, प्राधिकरण ग्रे और ओटीटी बाजारों से लगातार खतरे के प्रति भी सचेत है। इसलिए, आईटीसी की दर में किसी भी वृद्धि को इन दो विरोधी कारकों के बीच कैलिब्रेट किया जाना चाहिए।

53. बहुत अधिक उच्चतम सीमा ग्रे मार्केट ऑपरेटरों को प्रोत्साहित कर सकती है, और अगर एफएपी आईटीसी में इस वृद्धि को अपने ग्राहकों को पास करती है, तो यह कैरियर से ओटीटी रूट के लिए आईएलडी वॉइस ट्रैफिक के डायवर्जन को बढ़ा सकती है। यह न सेवा प्रदाताओं के हित में होगा और न ही पूरे देश के हित में। इसके अतिरिक्त, एक सेवा प्रदाता उच्च आईटीसी दरों को बनाए रखने का इच्छुक हो सकता है, जिससे विदेशी कैरियर के साथ मोलभाव में ज्यादा समय लग सकता है, जिसके परिणामस्वरूप

कभी-कभी बाजार में अनिश्चितता और विवाद उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, आईटीसी दर को भारतीय रुपये के स्थान पर, यूएस डॉलर में तय करने का सुझाव भी उचित नहीं है क्योंकि यह भारत के भीतर भारतीय पहुंच सेवा प्रदाताओं और आईएलडीओ के बीच एक सेटलमेंट है। इसलिए, कुछ इष्टतम मूल्य पर उच्चतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि इन चिंताओं का समाधान किया जा सके। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, प्राधिकरण का मत है कि उच्चतम सीमा एक ऐसे स्तर पर तय की जानी चाहिए जो पहले से पहचाने गए निम्नलिखित तीन उद्देश्यों को पूरा करता हो:

- (क) आउटगोइंग इंटरनेशनल कॉल पर टैरिफ को कम करने के लिए टीएसपी को बढ़ावा देना;
- (ख) ओटीटी हितधारकों के लिए ट्रैफिक के डायवर्जन को रोकना और ग्रे मार्केट के लिए मध्यस्थ अवसर नहीं बनाना, और
- (ग) विदेशी विनिमय दर भिन्नता के प्रभाव को निष्प्रभावी बनाना।

54. अधिकांश हितधारकों ने आईटीसी की दर को 0.75 रु. प्रति मिनट तक बढ़ाने का सुझाव दिया है तो कुछ ने 3.50 रु. प्रति मिनट तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, आईटीसी की दर में बेतहाशा वृद्धि किसी भी हितधारक के हित में नहीं हो सकती है। जैसा कि पैरा 32 में निष्कर्ष निकाला गया है, प्राधिकरण का इरादा पूर्व निर्धारित सीमा के भीतर आईटीसी की दर तय करने का है। अब सवाल यह है कि आईटीसी के लिए सीमा क्या होनी चाहिए। एक उचित दृष्टिकोण यह हो सकता है कि प्रस्तावित सीमा आईटीसी की वर्तमान दर और अंतिम संशोधन से पहले प्रचलित दर के बीच तय की जाए। यहाँ यह कहना उचित होगा कि अंतिम संशोधन से पहले की दर (0.53 रु. प्रति मिनट) का क्रमिक संशोधनों के माध्यम से एक अवधि में विकास हुआ था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, शुरुआत में, वर्ष 2003 में, आईटीसी और डीटीसी की दरें समान मूल्य पर निर्धारित की गई थीं, अर्थात् 0.30 रु. प्रति मिनट। इसके बाद, 2009 में, पहली बार, आईटीसी और डीटीसी की दरों को अलग-अलग मूल्यों पर तय किया गया था और हालांकि डीटीसी की दर को घटाकर 0.20 रु. प्रति मिनट कर दिया गया था, जबकि आईटीसी की दर को बढ़ाकर 0.40 रु. प्रति मिनट किया गया था। विदेशी मुद्रा दर भिन्नताओं का लागू करने के बाद, 0.40 रु. प्रति मिनट की दर को वर्ष 2015 में फिर से संशोधित करके इसे 0.53 रु. प्रति मिनट किया गया था। तदनुसार, पिछले संशोधन से पहले की प्रचलित दर विदेशी मुद्रा दर समायोजन के साथ 2009 से जारी थी। आईटीसी की वर्तमान दर पर निम्न सीमा, सेवा प्रदाताओं के मौजूदा राजस्व की रक्षा करेगी। इसके अलावा, इन दरों का पहले परीक्षण किया जा चुका है जिससे बाजार में कोई व्यवधान आने की संभावना नहीं है। यह न केवल विनियामक निश्चितता सुनिश्चित करेगा बल्कि सेवा प्रदाताओं को आवश्यक लचीलापन प्रदान करेगा। इसके अलावा, इन दरों को विदेशी मुद्रा दर भिन्नताओं के लिए समायोजित किया जाना चाहिए। अंतिम संशोधन से पहले, जब आईटीसी की दर 53 पैसे प्रति मिनट तय की गई थी, यूएसडी के लिए विनिमय दर 62 रुपये प्रति डॉलर थी। यह दर अब लगभग 75 से 76 रु. प्रति अमेरिकी डॉलर है। इसलिए, 53 पैसे के लिए विदेशी मुद्रा दर भिन्नता समायोजन लगभग 65 पैसे के बराबर होगी। इसी तरह, 30 पैसे के लिए समतुल्य विदेशी मुद्रा दर भिन्नता समायोजन लगभग 35 पैसे होगी। इसलिए, आईटीसी की दर के लिए 35 से 65 पैसे प्रति मिनट की सीमा सबसे उपयुक्त होगी।

55. कुछ एकल आईएलडीओ ने सुझाव दिया है कि यदि प्राधिकरण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कॉल के लिए असममित समापन प्रभार रखने का फैसला करता है, तो घरेलू समापन प्रभार के अलावा प्रभारित की गई अतिरिक्त राशि को आईएलडीओ और पहुंच सेवा प्रदाता के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। यह मांग करते हुए, उन्होंने यह तर्क भी दिया है कि यह उनकी जीविका के लिए भी जरूरी है क्योंकि बाजार में कैरिज प्रभार 4.5 पैसे के निम्न स्तर पर पहुंच गया है। यहां यह कहना उचित होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईएलडीओ के लिए राजस्व का प्राथमिक स्रोत कैरिज प्रभार है, जिसे फोरबेयरंस में रखा गया है। यह एकल के साथ-साथ एकीकृत आईएलडीओ पर भी समान रूप से लागू होता है। तदनुसार, आईएलडीओ आईएलडी कॉल के लिए कैरिज दर तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो उनके निवेश पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करता है। एकल और एकीकृत आईएलडीओ को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण यह अधिदेशित कर रहा है कि एक पहुंच सेवा प्रदाता, चाहे वो बेसिक सर्विस ऑपरेटर (बीएसओ), सेलुलर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर (सीएमएसपी), यूनिफाइड एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर (यूएसएसपी) हो या यूनिफाइड लाइसेंस (यूएल) लाइसेंसधारी हो, सभी को अर्थात् अपने संबद्ध आईएलडीओ और एकल आईएलडीओ को समान

- दर ऑफर करेगा। इस प्रावधान का किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उल्लंघन करने वालों पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
56. चूंकि आईएलडीओ बाजार में प्रतिस्पर्धा के अनुसार कैरिज दर तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो परिचालन की अपनी लागत को वसूल कर सकते हैं और लाभ की उचित राशि सुनिश्चित कर सकते हैं, आईएलडीओ के साथ समापन प्रभार शेयर करने और आईएलडीओ के लिए अलग प्रति मिनट प्रभार तय करने के रूप में इस समय पर किया गया कोई भी विनियामक हस्तक्षेप कैरिज प्रभार के लिए फ्लोर मूल्य रखने का कारण बन सकता है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। तदनुसार, प्राधिकरण की राय में, एकल आईएलडीओ की यह मांग उचित नहीं है। प्राधिकरण का मानना है कि आईटीसी में भारतीय आईएलडीओ और पहुंच सेवा प्रदाता के बीच किसी भी राजस्व हिस्सेदारी को निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
57. इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि आईटीसी की दर को 0.35 रु. प्रति मिनट से 0.65 रु. प्रति मिनट की निर्धारित सीमा के भीतर फोरबेयरंस में रखा जाएगा।
58. चूंकि देश में पहली बार आईटीसी की दर के लिए यह नई विनियामक व्यवस्था निर्धारित की जा रही है, इसलिए प्राधिकरण इसके कार्यान्वयन पर कड़ीबी नजर रखेगा, जिसमें देश में आईएलडी वॉइस ट्रैफिक के रुझान और पैटर्न भी शामिल हैं। प्राधिकरण, यदि जरूरी समझा गया, तो उचित समय पर इस व्यवस्था के साथ-साथ आईटीसी की दर की समीक्षा कर सकता है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2020

The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Sixteenth Amendment) Regulations, 2020 (4 of 2020)

F. No. 6-19/2019-BB&PA.—In exercise of the powers conferred upon it under Section 36, read with subclauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of 2003), namely:

1. (i) These regulations may be called the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Sixteenth Amendment) Regulations, 2020 (4 of 2020).
(ii) They shall come into force from the 1 st May, 2020.
2. In Regulation 4 of the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of 2003) (hereinafter referred to as the principal regulations), after clause (v), the following clause shall be inserted: “(vi) Every BSO, CMSP, UASP and Unified License (UL) licensee shall offer a termination charge, for international calls terminating on its network, in a non-discriminatory manner and within the range specified in Schedule I.”
3. In Schedule I of the principal regulations, in paragraph 1 in the table under column “Termination Charge”, for the words and figures “Re. 0.30 (paise thirty only) per minute”, the words and figures “Not less than Re. 0.35 (paise thirty five only) per minute and not more than Re. 0.65 (paise sixty five only) per minute” shall be substituted.

S. K. GUPTA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./07/2020]

Note 1. The principal regulations were published vide F.No. 409-5/2003-FN dated 29.10.2003 (4 of 2003) and subsequently amended vide notification Nos. --

- (i) 409-5/2003-FN dated 25.11.2003 (5 of 2003) (First Amendment);
- (ii) 409-5/2003-FN dated 12.12.2003 (6 of 2003) (Second Amendment);
- (iii) 409-5/2003-FN dated 31.12.2003 (7 of 2003) (Third Amendment);
- (iv) 409-8/2004-FN dated 06.01.2005 (1 of 2005) (Fourth Amendment);
- (v) 409-8/2004-FN dated 11.04.2005 (7 of 2005) (Fifth Amendment), which has been set aside by Hon'ble TDSAT vide its Order dated 21.09.2005 in appeal No. 7 of 2005;
- (vi) 409-5/2005-FN dated 23.02.2006 (1 of 2006) (Sixth Amendment);
- (vii) 409-5/2005-FN dated 10.03.2006 (2 of 2006) (Seventh Amendment);
- (viii) 409-2/2007-FN dated 21.03.2007 (2 of 2007) (Eighth Amendment);
- (ix) 409-22/2007-FN dated 27.03.2008 (2 of 2008) (Ninth Amendment);
- (x) 409-12/2008-FN dated 09.03.2009 (2 of 2009) (Tenth Amendment);
- (xi) 409-8/2014-NSL-1 dated 23.02.2015 (1 of 2015) (Eleventh Amendment);
- (xii) 409-8/2014-NSL-1 dated 24.02.2015 (2 of 2015) (Twelfth Amendment);
- (xiii) 10-8/2016-BB&PA dated 19.09.2017 (5 of 2017) (Thirteenth Amendment);
- (xiv) 10-8/2016-BB&PA dated 12.01.2018 (2 of 2018) (Fourteenth Amendment);
- (xv) 6-14/2019-BB&PA dated 17.12.2019 (10 of 2019) (Fifteenth Amendment).

Note 2. The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Sixteenth Amendment) Regulations, 2020 (4 of 2020).

**Explanatory Memorandum to “The Telecommunication Interconnection Usage Charges
(Sixteenth Amendment) Regulations, 2020”**

A. Interconnection

1. Interconnection means the commercial and technical arrangements under which service providers connect their equipment, networks and services to enable their customers to have access to the customers, services and networks of other service providers.
2. Interconnection is extremely important from a consumer's perspective. Subscribers of different service providers or network operators cannot communicate with each other or avail the services they demand unless essential interconnection arrangements are in place. Commercial and technical arrangements must be made to facilitate interconnection between network operators. Several issues must be agreed upon by the operators or determined by the regulator in order to finalize these arrangements. Interconnection is one of the foundations of viable competition and is very much essential for orderly growth of the telecommunications sector.

B. Interconnection Usage Charge (IUC)

3. Interconnection Usage Charge (IUC) is one of the most important commercial issue for a successful interconnection arrangement. A brief description of the various components of IUC is explained underneath.

(1) Domestic Termination Charge

4. Domestic termination charge (DTC) is the charge payable by an access provider, whose subscriber originates the call, to the access service provider (ASP) in whose network the call terminates. In a Calling-Party-Pay (CPP) regime, the calling subscriber pays for the call to his access provider and the calling party's access provider usually pays the termination charge to the called party's access provider to cover the network usage cost.

(2) International Termination Charge

5. International termination charge (ITC) is the charge payable by an Indian International Long-Distance Operator (ILDO), who carries the call from outside the country, to the access provider in the country in whose network the call terminates.

(3) Transit Charge

6. When two telecom networks are not directly connected, an intermediate network is used through which calls are transmitted to the terminating network. Such an intermediate network is known as a transit network, and the charges to be paid to the transit network to cover the interconnection/network usage cost are called transit charges.

(4) Carriage Charges

7. Access providers in India can offer access services within the Licensed Service Areas (LSAs), also known as circles; the inter-circle traffic is required to be routed through a National Long-Distance Operator (NLDO). The charges to be paid by an access provider to the NLDO to cover the cost for carrying the inter-circle calls are called carriage charges.

(5) Origination Charges

8. The calling party's access provider collects call charges from the calling party (i.e. the subscriber) as per the applicable tariff. From the amount so collected from the subscriber, the access provider has to pay termination charges to the called party's access provider and carriage charges (in case of an inter-circle call) to the NLDO. The access provider retains the balance amount to cover the cost of originating the call. The amount so retained by the calling party's access provider is called an origination charge. In India, origination charges have not been specified by the regulator and are under forbearance.

(6) International Settlement Charge

9. International settlement charges are the charges exchanged between foreign service providers and Indian ILDOs for exchanging international traffic. The international settlement charge includes international carriage charge, national carriage charge (if any), and the domestic termination charge.

C. Evolution of regulatory regime for ITC In India

10. Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter, referred to as, TRAI or the Authority) established a regulatory framework for Interconnection Usage Charges, including ITC through 'The Telecommunication Interconnection Usage Charges (IUC) Regulation, 2003 (1 of 2003)' dated 24.01.2003. For further improving and streamlining the IUC regime, the Authority issued 'The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of 2003)' dated 29.10.2003. This Regulation, which superseded the earlier IUC Regulation dated 24.01.2003 and came into effect from 01.02.2004, is the principal IUC regulation in the country as on date. There have been 15 (fifteen) amendments to this regulation since its inception.
11. Through 'The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of 2003) dated 29.10.2003', the Authority, *inter-alia*, prescribed ITC as Re. 0.30 per minute. Since then, the Authority has made three revisions in ITC as below:
 - (a) revision of ITC to Re. 0.40 per minute with effect from 01.04.2009 through the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Tenth Amendment) Regulations, 2009,
 - (b) revision of ITC to Re. 0.53 per minute with effect from 01.03.2015 through the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Eleventh Amendment) Regulations, 2015 and
 - (c) revision of ITC to Re. 0.30 per minute with effect from 01.02.2018 through the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Fourteenth Amendment) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as IUC Regulations, 2018).

D. The present exercise for review of ITC

12. In 2018, while analyzing the issues involved in deciding the ITC, the Authority noted that:
 - (a) carrier route for carrying international incoming voice traffic is facing a fierce competition from Over-The-Top (OTT) route and grey route; and
 - (b) international incoming voice traffic through carrier route has begun to decline from F.Y. 2016-2017.

13. The Authority further noted that if the arbitrage opportunity i.e. the difference between ITC and tariff for domestic voice call is plugged or kept to a minimum, the attractiveness of the grey route for carrying international incoming voice traffic would subside, and thereby, the carrier route for international incoming traffic would witness a legitimate growth. Accordingly, the Authority in the Explanatory Memorandum (EM) annexed to the IUC Regulations, 2018 has noted that:

“The Authority would closely monitor the trends and patterns of ILD voice traffic in the country. The Authority, if it deems necessary, may review ITC from time to time”.
14. In view of the above, the Authority has been continuously monitoring the developments in telecommunications market, and the trends in incoming and outgoing International Long Distance (ILD) voice traffic volume. To analyse the trends in incoming and outgoing ILD voice traffic volume, from time to time, the Authority collected the data pertaining to international incoming and outgoing voice traffic through carrier route. The analysis of this data indicates that the rate of decline of international incoming voice traffic through carrier route has reduced after the revision of ITC rate in 2018. As far as outgoing ILD voice traffic from India is concerned, it is much less in comparison to incoming ILD voice traffic. The outgoing ILD voice traffic has shown only marginal reduction. Further, in-line with the global trend, and with the rapid increase of data-enabled subscribers in India, the use of OTT communication applications for voice calling has increased. As most of the OTT communication applications do not charge for voice calls, the increase in OTT voice traffic might also be affecting the grey-market operations.
15. In the last few years, it has also been observed that the telecommunications market structure in India, as well as globally, has transformed from a voice to a data-centric market. The trend towards convergence of services like triple-play offerings (video, voice and data) has brought about a major shift in the pricing strategies of service providers, resulting in the growing prevalence of bundled tariffs. During this period, in India, it has also been noted that most of the mobile tariff offers have moved to bundled plans i.e. they include voice call minutes, SMS and data. Similarly, in the case of international roaming, tariff packages in the form of bundles comprising of certain pre-fixed quantity of incoming and outgoing voice calls, data, and messages are becoming popular. In view of these developments in the tariff offerings, it appears that at the retail level, the relevance of per unit rates of individual product i.e. voice, data, and messages is reducing.
16. The above-mentioned developments raise the question that whether the present regulatory regime for ITC prescribing a uniform rate on per minute basis is still relevant or there is a requirement of some changes in this regime. Should Indian ILDOs be provided with the flexibility for negotiation with international carriers? What could be the impact of such changes on the carrier-route traffic, and tariff of telecommunication services for Indian consumers? To discuss all these points, and any other relevant issue with the stakeholders, the Authority considered it significant to review the existing regulatory regime for ITC.
17. With this background, the Authority issued a consultation paper (CP) on “Review of Interconnection Usage Charges” dated 08.11.2019 to seek the views of stakeholders. Stakeholders were asked to submit their written comments by 09.12.2019 and counter-comments by 23.12.2019.
18. Comments and counter-comments received from TSPs, industry associations and other stakeholders, including companies, organizations, firms, and individuals were placed on TRAI’s website (www.trai.gov.in). An open House Discussion was held on 03.02.2020 at New Delhi to discuss the issues with all stakeholders. All the comments and counter comments received till date on this issue have been considered by the Authority before arriving at a conclusion. An analysis of the issues relating to ITC, based on the comments of stakeholders received in the consultation process and further deliberations, is presented below.

E. Analysis of the comments on the issues raised in the CP

19. In the CP dated 08.11.2019, the Authority had sought the views of stakeholders on the following issues related to IUC:
 - i. (Q1): Keeping in view the changes happening in the international telephony market structure, is there a need for change in the existing regulatory regime for International Termination Charge (ITC) i.e. change the existing regulatory regime from fixing the uniform rate of ITC to an alternate approach? Kindly justify your comments with supporting arguments.
 - ii. If your response to Q1 is affirmative, then what should be the alternate approach? Kindly elucidate the alternate approach and benefits of the same vis-à-vis the present approach.

- iii. If your response to Q1 is negative, then in the changing international telephony market structure, what other regulatory measures are required to be taken by the regulator for protecting the interests of Indian consumers and service providers? Kindly justify your comments with supporting arguments.
 - iv. Your comments on any other issue related to the international termination charges may also be given.
20. During the consultation process, majority of the stakeholders were in favour of an increase in the ITC rate. As per their perspective, it would help Indian access service providers in offering more affordable ISD tariffs to their customers, generate more forex to the country and more revenue to the exchequer. However, there is a difference of opinion among these stakeholders as far as the regulatory regime for ITC is concerned. Some of them favoured the continuation of the existing regulatory regime of fixed uniform rate of ITC with an increase in termination charges whereas others favoured an alternate regulatory regime, such as forbearance with an upper ceiling or forbearance within a prescribed range.
21. While most of the stakeholders contended that ITC rate should be increased from its present level of Re. 0.30 per minute; a few of them have argued that ITC should be brought down to the level of Domestic Termination Charge (DTC). One of the consumer organisations has even advocated for total elimination of ITC. It is worth mentioning that at present the DTC is as below:
- (a) Re. 0.06 per minute for wireless to wireless calls; and
 - (b) Zero for wireline to wireless, wireless to wireline and wireline to wireline calls.

Summary of the suggestions given by the stakeholders during the consultation process and their analysis is presented below.

(I) Review of the existing regulatory regime:

22. According to a stakeholder, massive increase in data services adoption, prevalence of bundled tariff plans, rapidly increasing OTT penetration, unrelenting trend of decline of international incoming voice traffic through carrier route with an emerging trend of fall in outgoing traffic from India implies that timing is apt for a review of ITC. This stakeholder further added that the Authority's good intention behind the reduction in ITC in 2018 has been defied by various players in the international traffic value chain. According to this stakeholder, the substantial reduction of over 43% in ITC was never passed on by foreign service providers to end users and the call charges to India remained static or increased despite the reduction in the ITC rate.
23. Some of the stakeholders are not in favour of alternate regulatory regimes for ITC such as forbearance regime or reciprocal termination rates regime. They are of the opinion that with forbearance granted on ITC rate, a service provider might be tempted to keep high ITC rates leading to protracted negotiations with foreign carriers. Similarly, another alternative of reciprocal termination rates regime has the potential of leading to a price-hiking race, which can lead to traffic routing through countries having favourable termination rates. Hence, they are of the view that fixed ITC is the optimum approach. These stakeholders have recommended for increase in ITC rate stating that it would not impact Indian customers and on the other hand would result in an increased inflow of forex to the Indian operators yielding increased revenues to the exchequer.
24. One state-owned TSP has submitted that evaluation of IUC should be based on actual costs, and such costs should include HR costs also. While deciding any aspects of termination charges, TRAI should consider the network costs of PSUs. It added that since the incoming and outgoing ILD traffic minutes is consistently reducing due to various reasons, further reduction in ITC by way of direct reduction or by other ways like implementing forbearance principle will result in further losses to TSPs due to substantial non-recovery of network costs. This stakeholder has requested that the present regulatory provisions for ILD Termination Charges may be continued. However, if considered necessary, the rates for ILD termination charges may be fixed over a range introducing the traffic-volume slabs.
25. A TSP argued that with the international telephony structure shifting towards OTT, there may also be a need for shifting from fixed uniform approach to an alternate approach. According to this TSP, such approach should be forbearance in ITC within a prescribed range. In the said TSP's view, such prescribed range, at minimum, should be Re. 0.75 to Rs.1.25.
26. One stakeholder of the same opinion has said that the competition in this segment is high and there are many factors which are not under the control of regulator including the challenges from OTT. In this scenario, the option of forbearance, with upper ceiling determined by TRAI, will give better negotiating power to the TSPs and to deal with the challenges from OTT. In its view, TSPs can also negotiate with other TSPs in our country or of other countries on either volume based or flat-rate charges. It has

suggested for forbearance of ITC for incoming international long-distance call in India, as it is adopted in many countries and also in the case of outgoing international long-distance calls in India. The international carriage charges and international termination charges at the foreign end are also under forbearance.

27. Another stakeholder has said that the strategy to curb the grey market, and increasing traffic on the carrier route by reducing the ITC appears to have met with limited success. It has argued that for an international incoming call, either through a regulated rate or in case of a forbearance regime, the rate should be driven domestically and not by the foreign access providers (FAPs). In case of forbearance regime, to safeguard the risks of unpredictable behaviour by service providers and that of unprecedented changes in the ITC rate affecting other sectors of economy, it has advocated for forbearance approach with a ceiling rate for ITC.
28. It can be observed from the above-mentioned points that while most of the stakeholders suggested for review of the ITC, their opinions are divided in respect of regulatory regime to be followed for ITC. While some stakeholders suggested to continue with the existing regime of uniform ITC rate, many other stakeholders have suggested alternate approaches. Broadly, the stakeholders have commented about the following five approaches, viz:
 - (a) continue with the existing regulatory regime of fixed uniform ITC;
 - (b) keep ITC under complete forbearance;
 - (c) Keep reciprocal ITC rates i.e. the same rate of ITC at Indian and the foreign end;
 - (d) keep ITC under forbearance with an upper ceiling; and
 - (e) keep ITC under forbearance within a pre-specified range.
29. The Authority is conscious of the fact that any incoming call (including international incoming call) is a monopoly of the called party's access service provider (i.e. the access service provider whose customer receives the incoming call). In case ITC is left under complete forbearance, the called party's access service provider may try to obtain higher termination charge, as high as possible from the ILDOs. This charge in-turn would be passed on by ILDOs to FAPs. Beyond a certain limit, FAPs may pass on such increase in the rate of ITC to their subscribers by increasing the tariff for India-bound outgoing ILD calls. This could further accelerate shifting of ILD traffic from carrier route to OTT route. Therefore, increasing the rate of ITC indiscriminately may not be in the interest of any stakeholder. Accordingly, this approach is completely ruled out.
30. As far as the reciprocal ITC rate approach is concerned, the stakeholders have enumerated reasons against this approach. This regime has the potential of leading to a price-hiking race, which can further lead to traffic routing through countries having favourable termination rates. In such cases, the identity of originating call location is hidden which will lead to falsification of Calling Line Identification (CLI), which has larger security implications. Accordingly, the Authority is of the view that this approach might create more uncertainty and disruption in the ILD market. Thus, this approach is completely ruled out.
31. As far as the existing regulatory regime of fixed uniform ITC is concerned, while it ensures ease of operations, it restricts the required flexibility to service providers in the fast changing ILD market. Due to pre-fixed rate of ITC, the Indian operators are not able to negotiate termination rates, with their foreign counterparts for termination at foreign end, which is under forbearance. Further, fixed uniform ITC approach requires frequent interventions of the Authority as the underlying factors such as forex rates, traffic pattern, termination charge at foreign end etc. keep on changing in the open market. This regime was more suitable when most of the ILD traffic was routed through carrier route only. Now, with the advent of newer technologies, when OTT route has emerged as an alternate for ILD voice calls, the Authority is of the view that some flexibility to service providers in deciding the rate of ITC would be in the interest of the telecom sector. Service providers may use this flexibility to discover the optimal rate of ITC, which not only helps in increasing the traffic through carrier route, as it is in their interest, but also disincentivises grey-market operations.
32. Having ruled out the first three options discussed, for deciding the rate of ITC in para 28 above, the remaining options are forbearance with an upper ceiling and forbearance within pre-specified range. As mentioned earlier, since the incoming ILD traffic is much higher than outgoing ILD traffic, the ITC constitutes a significant source of revenue for Indian TSPs. Therefore, it is imperative that while deciding an alternate regulatory regime for ITC, regulatory certainty is also ensured. In an open market, where the size of the market participants varies considerably, the corresponding negotiation power also varies. This is also reflected in the comments of different stakeholders. At this point of time, opting for

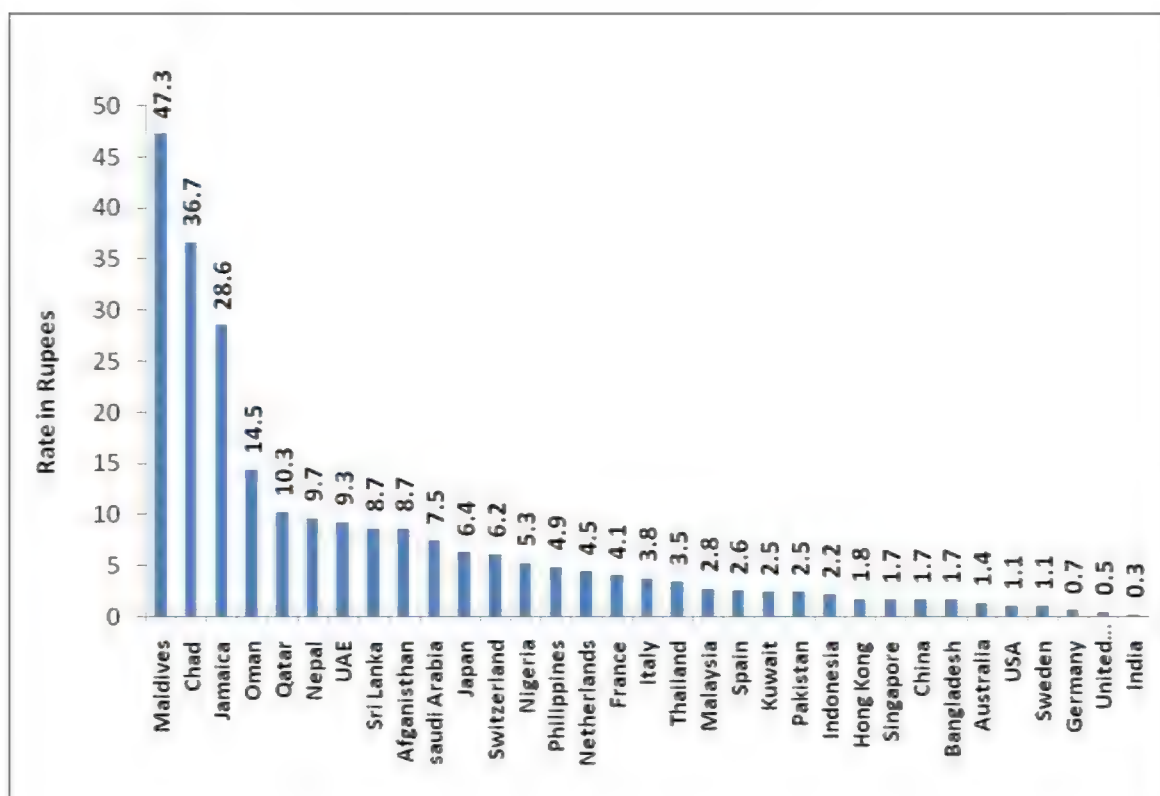
forbearance with an upper ceiling only approach may give rise to uncertainties about this important source of revenue, especially to smaller operators. If such operators are not able to negotiate better rates, then their existing revenue from this source may also get affected. Therefore, in view of the Authority, at this point of time, when we are transitioning from fixed uniform ITC regime, forbearance within pre-specified range would be a better option. To a large extent, this would also address the concerns of such stakeholders who are advocating for continuation of fixed uniform ITC regime as this is the nearest alternate approach, which also provides the required flexibility to service providers to face the emerging challenges in the market. Such flexibility provided to service providers may help them in designing innovative tariff models in the interest of their subscribers.

33. In the ILD voice telephony market, presently in India, we primarily have two types of ILDOs. First are the ones who operate only in the ILD space, and second are the ones who operate in the Access Service as well as ILD space. In the revised regulatory regime for ITC i.e. forbearance within pre-specified range, it would be necessary for access service providers, also having ILD operations, to offer matching termination rates in transparent and non-discriminatory manner to stand-alone ILDOs. Any form of discrimination on this account would not be permitted and if deemed necessary, a suitable investigation as per the provisions of TRAI Act, 1997, with consequent penal action, may be initiated.

(II) Rate of ITC:

34. Some stakeholders argued that ITC rate in India at Re. 0.30 per min. is probably the lowest in the world. According to them even neighbouring SAARC countries like Bangladesh, Pakistan, Nepal and Sri Lanka have an average blended ITC rate of nearly Rs. 4 to Rs. 6.50 per min. While in Middle East the average blended ITC rate is much higher at Rs. 8 to Rs. 9 per min. As per these stakeholders, only few countries have comparable ITC rates, though still much higher than India. These stakeholders have supported their arguments with the following global trend of International termination charge rates:

Figure 1: Global International Termination rates



Source: A TSP provided through its comments

Thus, as per these stakeholders, on an average, Indian Operators pay Rs. 3.0 to Rs. 3.50 per min. to the foreign access providers (FAPs) for termination of calls originating from India and TRAI's fixation of ITC for Indian access providers at Re. 0.30 per min. is less than 10% of the world's average.

35. One of the TSPs argued that the Authority, while deciding on reducing the ITC rate from Re. 0.53 per min. to Re. 0.30 per min, had considered curbing of grey route as the most important regulatory priority

- so that the Indian terminating traffic through carrier route increases. But, even after this reduction in ILD termination charge, the ILD incoming minutes through carrier route continues to decline at a greater rate.
36. Another TSP argued that in many countries, FAPs have commercially negotiated rates with international carriers. As per this TSP, the cost of outbound calls from India to Indian ILDOs is very high and majority of which is attributable to charging by FAPs for call termination on their networks. FAPs are earning many times more than Indian Access Operators for both origination and termination. Accordingly, as per this TSP, it is reasonable to increase the rate of ITC which will help in meeting the prime objectives as set out in the CP.
 37. According to a stakeholder, over the two years period since last review, increase in ITC by telcos in Europe, Africa, Asia-Pacific, etc. has resulted in higher pay outs by Indian access service providers and in-turn charging of higher rates in the form of ISD tariff from Indian customers. It further added that a lower termination charge does not ensure parity for Indian TSPs. Accordingly, as per this stakeholder, with the increase in the ILD costs to be paid to foreign operators and decline in ILD revenues from customers, the overall impact on the operators has been hugely negative.
 38. Some stakeholders argued that ITC rate, lower than the world average, causes lower revenues for the Indian access providers in comparison to their foreign counterparts. In support of this argument, one TSP said that in FY 2016-2017, with ITC at Re. 0.53 per minute, the net forex gains to the country was to the tune of Rs. 3675 crores considering receivable from foreign operators on account of ITC and payable to the foreign operators for outgoing international calls. According to this TSP, in FY 2018-2019, the net forex gains to the country has reduced to Rs. 950 crores, causing an overall reduction in forex gains by approximately 75%. Hence, according to these stakeholders, reduction in ITC rate has resulted in a significant loss to the Government and the nation in terms of forex.
 39. According to a service provider, since different countries charge different ISCs, the termination charge for an incoming international call to India should be ideally under forbearance while varying with region/country. But it might be a challenge to implement origin-based ITC as the calls are being transited through hubs by the various aggregators/foreign ILDOs. In view of the same, this service provider has recommended that the ITC should be raised to Re. 1 per minute on an immediate basis and be subsequently raised to Rs. 3 to Rs. 3.50 per minute, i.e. equivalent to the charges paid by the Indian access service providers for the termination of ILD calls in foreign countries.
 40. Majority of the TSPs are of the opinion that grey-market concerns do not warrant reduction in ITC. One TSP has argued that with stringent subscriber verification, due analytics carried out by operators and regular reporting to LSA (License Service Area) units of DoT, the grey-market concerns are already being addressed. In their view, as far as the security issues related to grey market are concerned, cost is not a concern for those who want to exploit this channel. Hence, according to these stakeholders, by reducing the arbitrage, we cannot eliminate the grey-market operation specially setup with an intent to bypass the security requirements.
 41. Some stakeholders are of the view that, in respect of ILD calls, substitution from carrier to OTT route is not reducing in the global context. While, there is continuous reduction in International voice traffic through Carrier route, continuous rise has been noticed in the International voice traffic through OTT route in the last few years. In support of this argument one TSP has provided a year-on-year

comparison of estimated traffic carried through carrier vs. OTTs route in billions of minutes, which is reproduced in the Table 1.

Table 1: Total traffic carried through carrier Vs. OTTs route in billions of minutes

Year	Carrier Traffic	OTT Traffic	% increase in Carrier Traffic	% increase in OTT Traffic
2015	553.3	418.5		
2016	527.9	570.3	-4.6%	36.3%
2017	483.8	757.2	-8.4%	32.8%
2018*	449.9	952.4	-7.0%	25.8%

*2018 figures are projected figures

Source : Tele Geography 2019 Edition of 'the State of the Network'

Hence, according to this report, there is a continuous decline in the incoming international voice traffic through carrier route. Another TSP, who is also of the same opinion, has inferred that while growth in OTT for international calling is a global phenomenon, it has not forced the operators in foreign countries to reduce their termination rates. As per this TSP, the solution to this problem lies in regulating OTT players and not in cannibalizing our own legitimate revenue.

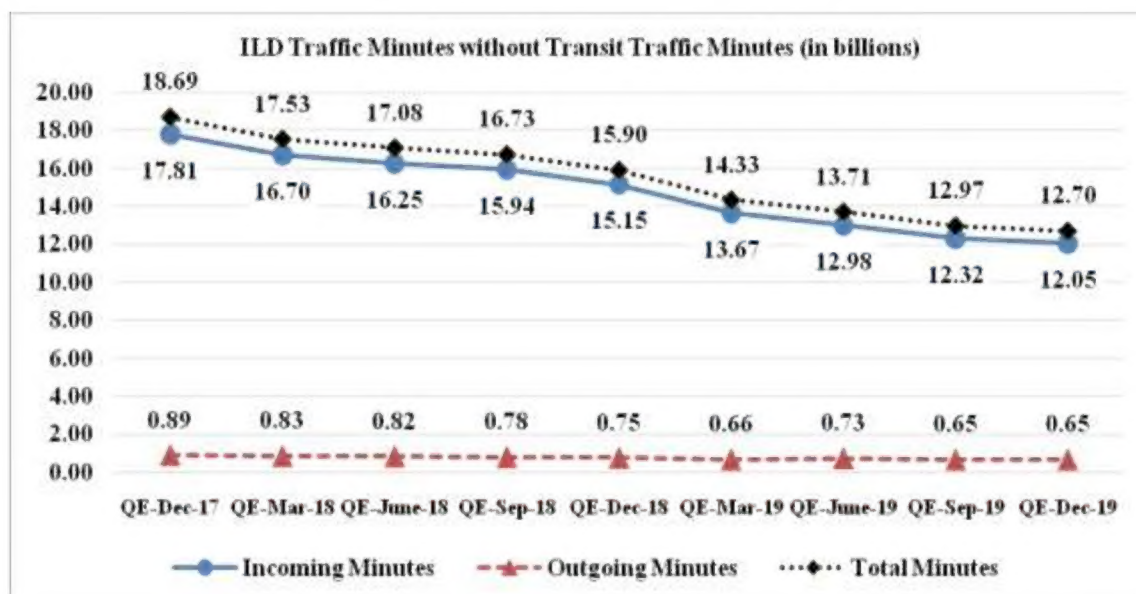
42. Another TSP in favour of continuing with the current regulatory regime of fixed ITC has proposed that the ITC should be rationalized considering various changes in the telecom landscape and should be increased to the range of Re. 0.65 to Re. 0.75 per minute. As per this TSP, the foreign operators have not passed on the benefits of 23 paise per min. reduction in the rate of ITC to their subscribers and have only increased their profit margins.
43. Another service provider stated that the termination charges in several countries are 8 to 10 times higher than the ITC in India and the dollar exchange rate variation from 2015 to 2019 is Rs. 62 to Rs. 71 and the Indian ILDOs pay the International Settlement Charges (ISC) in USD to foreign carriers for settlement of accounts. This service provider is of the opinion that the incoming termination rate which is presently Re. 0.30 per min. in India may be fixed in terms of U.S. Cents as 1 Cent/min which will give relief regarding forex variation in deducing the incoming IUC. This TSP has also advised that ITC in the country may be kept uniform for all terminating networks.
44. According to a consulting firm with the same opinion, in many countries across the world, where there is a significant volume of ILD traffic, the termination charges are kept under forbearance and are fixed by TSPs themselves as per negotiations. However, since the termination charges in India are fixed at a uniform rate, the FAPs have taken advantage of the situation with their comparatively higher rates and have practically become the price makers in their markets. According to this stakeholder, Indian ILDOs are earning lower revenue per minute from foreign operators, when cost per minute paid by the Indian ILDOs to the foreign operators is compared. In their opinion, the Indian markets should continue to keep a uniform rate, which could possibly reduce or eliminate re-routing of calls via low settlement rate countries and increase the termination charges. They have suggested an increase in ITC to INR 0.60 or INR 0.70 per minute at least based on the reasoning that internationally an approximate amount of \$0.5 is being paid.
45. As per the stand-alone ILDOs operating in the Indian market, they are facing the challenges of sustenance due to low-revenue margins, and have to bear the brunt of the exchange rate fluctuations as well as longpayment cycles in the international market. As per them, the Government and the Regulator has been helping out the ASPs who are facing the low margins. Similar help is needed specially for the ILDOs who do not have access to a large captive access network. They have requested that apart from the issues of traffic imbalance, grey market operation and traffic shifting to OTT application, interest of standalone ILDOs needs to be taken into consideration while deciding any regime on ITC. One such operator has suggested that any differential charge above the DTC should be mandated to be distributed between ILDO and ASP in the ratio of 60:40. As per this operator, if such distribution of differential revenue is not mandated by TRAI it will lead to vertical squeeze in international traffic. In its view, this would mean that standalone ILDO would not be able to compete against the integrated service providers. This stakeholder also suggested that the authority should actively engage with regulators in major traffic exchange countries for making a low-reciprocal arrangement for ITC between such

- countries. This would help reduce the cost of outgoing ILD calls for Indian subscribers and also help to shift the traffic back from OTT to PSTN.
46. Another standalone ILDO has argued that framework of IUC must be based on the principle of "Work Done". In its view, the current market situation is making it unviable for independent ILDOs to sustain. According to this ILDO, the market price for India termination being offered by some carriers is as low as 0.48 US cents (INR 0.345) which leaves a meagre margin of only 4.5 paisa for ILDOs because of the current ITC being INR 0.30. These settlement rates are unsustainable. In its view, the margins being made by ILDOs are not even sufficient to cover the cost of bandwidth being maintained by them for carriage of calls leave aside getting a reasonable return on their investments. Equipment and infrastructure involved at various stages in carriage of outgoing ILD calls from India and incoming calls to India have been elaborated in detail by this stakeholder. According to this ILDO, they need to significantly invest in infrastructure assets to manage the routing, billing and settlement of calls and monitoring systems to comply with the regulatory directives issued by DoT and the Authority. They have recommended to keep current ITC charges at INR 0.30 payable to access and mobile operators and allocate another INR 0.24 for ILDO for their investment and efforts.
 47. One stakeholder advocating reduction in ITC has stated that the work done for terminating the calls by ASP is same for domestic and international calls. In its view, ITC should be brought equal to Domestic Termination Charge (DTC) in two stages. It has suggested that in the first stage ITC may be reduced to 15 paisa per minute and in second stage it may be made equal to DTC. In its view it will help to discourage OTT calling, thereby arrest security concern and ultimately encourage competition among the operators
 48. It can be induced from the above that while most of the stakeholders have suggested for an increase in the rate of ITC, their opinions are divided in respect of revised rate. While a stakeholder has suggested to increase the rate of ITC up to Rs. 3.5 per minute, most of them have suggested to increase the rate of ITC up to Re. 0.75 per minute. Another stakeholder has suggested the range of Rs. 0.75 to 1.25 per minute for ITC rate. Few of them, while requesting an increase in the rate of ITC, have also suggested that the increased amount be earmarked to ILDOs and not to the Access Service Providers. One stakeholder has suggested for reducing the rate of ITC to the level of DTC.
 49. Before we examine the proposal to reduce the rate of ITC to the level of DTC, it would be worth to mention here that for the period beginning from 01.02.2004 up to 31.03.2009, the Authority prescribed ITC at par with DTC. However, from 01.04.2009 onwards, ITC was fixed at a level higher than the DTC as mentioned below:
 - (a) ITC at Re. 0.40 per minute with effect from 01.04.2009 to 28.02.2015 vis-à-vis DTC at Re. 0.20 per minute.
 - (b) ITC at Re. 0.53 per minute with effect from 01.03.2015 to 31.01.2018 vis-à-vis DTC at Re. 0.14/0.06 per minute.
 - (c) ITC at Re. 0.30 per minute with effect from 01.02.2018 till date vis-à-vis DTC at Re. 0.06 per minute.
 50. While prescribing differential rates for ITC and DTC, for the first time, through the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Tenth Amendment) Regulations, 2009, the Authority noted that cost-orientation of charges should not be the sole criteria for fixing ITC, the international termination charges prevalent internationally should also be taken into account. It should also be seen as to what is more advantageous to Indian operators and Indian consumers. Thereafter, when the Authority again prescribed differential rates for ITC and DTC through the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Eleventh Amendment) Regulations, 2015, it had noted that the ITC should be fixed at a level which meets three objectives viz. (a) encourage TSPs to reduce tariffs on outgoing international calls and prevent any pass-through to domestic tariffs of revenue losses arising from the calling card Regulation; (b) prevent the diversion of traffic towards OTT players such as Skype, Viber; and do not create arbitrage opportunity for grey market, (c) neutralize the effect of the foreign exchange rate variations. In 2018 also, all these factors were kept in mind by the Authority while revising the rate of ITC to Re. 0.30 per minute.
 51. The Authority is of the opinion that these factors continue their relevance even now. Therefore, to argue that the rate of ITC should be fixed on the work done principle alone is not tenable. Further, as per available data, when the reduction in the rate of ITC from Re. 0.53 to Re. 0.30 in 2018 has not reduced the incoming ILD traffic through OTT route, how bringing down the ITC to the level of DTC would address OTT and thereby security concerns is not clear. The stakeholder suggesting this measure has failed in giving any persuasive reason with supporting data. In fact, growth in OTT traffic

for international calling is a global phenomenon and most of the other countries have not reduced their international termination charges to the level of their DTC.

52. The Authority has collected data pertaining to incoming and outgoing ILD traffic from ILD operators, from time to time. Based on which, a quarter-on-quarter ILD traffic minutes is presented in Figure 2.

Figure 2 : ILD Traffic Minutes (in billions)



From Figure 2, it can easily be concluded that while the incoming and outgoing ILD traffic from India has reduced at different pace during the last two years, the imbalance between the incoming and outgoing ILD minutes is still substantial and stands at 18:1 i.e., the incoming ILD minutes in India is 18 times higher than the outgoing ILD minutes from India. Further, as elaborated earlier, Indian operators' per minute cost towards termination charges for outgoing ILD calls is much higher in comparison to the revenue earned by them from termination charge paid by foreign operators on per minute basis. ILDOs pass on the burden of higher termination rate of any country to the Indian Access providers, thereby limiting their ability to provide cheaper ISD rates to Indian customers. An increase in the rate of ITC would help reducing the pricing arbitrage which presently exists in favour of foreign operators. However, while considering any increase in the rate of ITC, the Authority is conscious of the constant threat from grey and OTT markets. Therefore, any increase in the rate of ITC must be calibrated between these two opposing factors.

53. A very high upper ceiling may encourage grey market operators, and if the FAPs pass on such increase in ITC to their customers then that may further accelerate the diversion of ILD voice traffic from carrier to OTT route. This would neither be in the interest of service providers in particular nor in the interest of the country as a whole. In addition to this, a service provider might be tempted to keep high ITC rates leading to protracted negotiations with foreign carriers sometimes resulting into uncertainty and disputes in the market. Further, a suggestion to fix the rate of ITC in terms of USD, in place of Indian Rupee, is not tenable as it is a settlement within India between Indian Access Service Providers and ILDOs. Hence, a ceiling must be set at some optimum value, so that these concerns may be addressed. In view of the foregoing discussions, the Authority is of the opinion that the upper ceiling should be fixed at a level which meets the already identified three objectives viz:
- encourage TSPs to reduce tariffs on outgoing international calls,
 - prevent the diversion of traffic towards OTT players and do not create arbitrage opportunity for grey market, and
 - neutralize the effect of the foreign exchange rate variation.
54. While most of the stakeholders have suggested to increase the rate of ITC up to Re. 0.75 per minute, few have suggested to increase up to Rs. 3.50 per minute. As discussed earlier, increasing the rate of ITC indiscriminately may not be in the interest of any stakeholder. As, concluded in para 32, the Authority intends to fix the rate of ITC within a pre-specified range. The question now is that what should be the range for ITC. A reasonable approach could be that the proposed range is fixed between the current rate of ITC and the rate prevalent before last revision. It is pertinent to note here that the rate (Re. 0.53 per minute) prevalent before last revision evolved over a period through successive revisions.

As mentioned earlier, initially in the year 2003, the rates of ITC and DTC were fixed at same value i.e. Re. 0.30 per minute. Subsequently, in 2009, for the first time, the rates of ITC and DTC were fixed at different values and while the rate of DTC was decreased to Re. 0.20 per minute, the rate of ITC was increased to Re. 0.40 per minute. This rate of Re. 0.40 per minute was further revised to Re. 0.53 per minute in the year 2015 after applying the forex rate variations. Accordingly, the rate prevalent before last revision was continuing since 2009 with forex rate adjustments. The lower ceiling at current rate of ITC would protect existing revenue of the service providers. Further, these rates are already tested and may not bring any disruption in the market. This would not only ensure regulatory certainty but also provide the required flexibility to service providers. Also, these rates must be adjusted for forex rate variations. Before last revision, when the rate of ITC was fixed at 53 paise per minute, the exchange rate for USD was Rs. 62 per dollar. That rate is now hovering around Rs. 75 to Rs. 76 per US dollar. Therefore, the forex rate variation adjusted equivalent of 53 paise would be approximately 65 paise. Similarly, the forex rate variation adjusted equivalent of 30 paise would be approximately 35 paise. So, the range of 35 to 65 paise per minute for the rate of ITC would be most appropriate.

55. A few standalone ILDOs have suggested that if the Authority decides to keep an asymmetric termination charge for domestic and international calls, the additional amount charged over and above the domestic termination charge should be divided in a 60:40 ratio between the ILDO and the access service provider. While demanding this, they have simultaneously argued that this is necessary for their sustenance as the carriage charges in the market have reduced to abysmally low level of 4.5 paise only. It is pertinent to note here that the primary source of revenue for ILDOs is carriage charges in the international leg, which is under forbearance. This is equally applicable to standalone as well as the integrated ILDOs. Accordingly, the ILDOs are free to decide the carriage rate for ILDO calls which ensures reasonable return on their investments. To ensure the level playing field between standalone and integrated ILDOs, the Authority is mandating that an access service provider, be it Basic Service Operator (BSO), Cellular Mobile Service Providers (CMSP), Unified Access Service Provider (UASP) or Unified License (UL) licensee, shall offer the non-discriminatory rate of ITC to everyone i.e. to its own associated ILDO as well as to standalone ILDOs. Any kind of direct or indirect violation of this provision may attract the penal action against violators as per the provisions of TRAI Act, 1997.
56. Since the ILDOs are free to decide the carriage rate, as per the competition in the market, which can recover their cost of operations and ensure reasonable amount of profit, any regulatory intervention at this point of time, by way of sharing termination charges with ILDOs or fixing separate per minute charges for ILDOs, would amount to putting a floor price for carriage charges. This may affect the competition in the marketplace. Accordingly, in view of the Authority, this demand of the standalone ILDOs is not tenable. The Authority is of the view that there is no need for prescribing any revenue share between Indian ILDO and access service provider in the ITC.
57. Keeping in view all these facts, the authority has decided that the rate of ITC shall be kept under forbearance within a prescribed range of Re. 0.35 per minute to Re. 0.65 per minute.
58. As this new regulatory regime for the rate of ITC is being prescribed for the first time in the country, the Authority would closely monitor its implementation, including the trends and patterns of ILDO voice traffic in the country. The Authority, if it deems necessary, may review this regime as well as the rate of ITC in due course of time.